



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42]
No. 42]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 18, 1986/आश्विन 26, 1908
NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 18, 1986/ASVINA 26, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (other than
the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक निकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 1986

का. आ. 3574.—केन्द्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
(1974 का 2) की धारा 24 के उपखण्ड (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए, श्री बी. वी. नडकरणी, अधिवक्ता, मुम्बई उच्च न्यायालय
को, अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, आठवां न्यायालय, मुम्बई के न्यायालय
में मैसर्स आर. के. सिंथेटिक फाइबर (प्राइवेट) लिमिटेड, के विरुद्ध
मामला सं. आर. सी. 17/68-मद्रास में अभियुक्त के अभियोजन का
संचालन करने के लिए विशेष सौत नियुक्त करता है।

[संख्या 225/7/86 ए. वी. डी. (II)
जी. सीतारामन, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. & PENSIONS
(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 1st October, 1986

S.O. 3574.—In exercise of the powers conferred by sub-
section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure,
1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints
Shri B. V. Nadkarni, Advocate, Bombay High Court as a
Special Public Prosecutor for conducting the prosecution of
the accused in case No. RC. 17/E/68-Madras against M/s.
R. K. Synthetic Fibre (P) Ltd. in the Trial Court at Bombay.

[No. 225/7/86-AVD.II]
G. SITARAMAN, Under Secy.

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 1986

सूचना

का.आ. 3575.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम
प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री विपिन चन्द्र एस. छत्रा,
एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन
इस बात के लिए दिया है कि उसे राजकोट (गुजरात) व्यवसाय करने के
लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार
का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में
मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5 (66)/86-न्याय]
आर. एन. पीटार, सक्षम प्राधिकारी

MINISTRY OF LAW & JUSTICE
(Department of Legal Affairs)
New Delhi, the 6th October, 1986

NOTICE

S.O. 3575.—Notice is hereby given by the Competent
Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules,
1956, that application has been made to the said Authority,
under rule 4 of the said Rules, by Shri Vipin Chandra S.
Chhatra Advocate for appointment as a Notary to practise in
Rajkot.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(66)/86-Judl.]

R. N. PODDAR, Competent Authority

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

नई दिल्ली, 5 जून, 1986.

(आय-कर)

का.प्रा. 3576.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ "वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया, बंगलोर" को कर निर्धारण वर्ष 1986-87 से 1988-89 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिये अधिसूचित करती है।

[सं. 6743/का.सं. 197/74/85-आ.क. (नि.-I)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 5th June, 1986

(INCOME-TAX)

S.O. 3576.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Wildlife Association of South India, Bangalore" for the purpose of the said Section for the period covered by the assessment years 1986-87 to 1988-89.

[No. 6743/F. No. 197/74/85-IT(AI)]

नई दिल्ली, 10 जून, 1986

(आय-कर)

का.प्रा. 3577.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ "आरोग्यवर्म डिवेलपमेंट सोसाइटी, मदनापल्ले" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिये अधिसूचित करती है।

[सं. 6748/का.सं. 197/12/86-आ.क. (नि.-I)]

New Delhi, the 10th June, 1986

(INCOME-TAX)

S.O. 3577.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Arogyavaram Development Society, Madanapalle" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 6748/F. No. 197/12/86-IT(AI)]

नई दिल्ली, 12 जून, 1986

(आय-कर)

का.प्रा. 3578.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "ज्ञान प्रबोधिनी, पुणे", को कर-निर्धारण वर्ष 1984-85 से 1988-89 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिये अधिसूचित करती है।

[सं. 6750/का.सं. 197/107/86-आ.क. (नि.-I)]

New Delhi, the 12th June, 1986

(INCOME-TAX)

S.O. 3578.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Jhana Prabodhini, Pune" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1984-85 to 1988-89.

[No. 6750/F. No. 197/107/86-IT (AI)]

नई दिल्ली, 16 जून, 1986

(आय-कर)

का.प्रा. 3579.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "व नेहरू ट्रस्ट फॉर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिये अधिसूचित करती है।

[सं. 6757/का.सं. 197/167/84-आ.क. (नि.-I)]

New Delhi, the 16th June, 1986

(INCOME-TAX)

S.O. 3579.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Nehru Trust for Cambridge University" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 6757/F. No. 197/167/84-IT(AI)]

नई दिल्ली, 20 जून, 1986

(आय-कर)

का.प्रा. 3580.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "ग्राम इण्डिया पिंगलवाड़ा सोसाइटी (रजिस्टर्ड) अमृतसर" को कर निर्धारण वर्ष 1986-87 से 1988-89 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिये अधिसूचित करती है।

[सं. 6767/का.सं. 197/26/86-आ.क. (नि.-I)]

New Delhi, the 20th June, 1986

(INCOME-TAX)

S.O. 3580.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "All India Pingalwara Society (Regd.), Amritsar" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1986-87 to 1988-89.

[No. 6767/F. No. 197/26/86-IT(AI)]

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1986

आय-कर

का.प्रा. 3581.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "डिफेंस विविलियम्स वेलफेयर (टी.बी. केंसर एंड सेप्रोसी) फंड" को कर निर्धारण वर्ष 1986-87 से 1988-89 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिये अधिसूचित करती है।

[सं. 6785/का.सं. 197/93/86-आ.क. (नि.-I)]

New Delhi, the 3rd July, 1986
(INCOME-TAX)

S.O. 3581.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Defence Civilians Welfare (T.B., Cancer and Leprosy) Fund for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1986-87 to 1988-89.

[No. 6785/F. No. 197/93/85-II(AI)]

(आयकर)

का.पा. 3582—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "कैन्सर रिलीफ सधिस, कलकत्ता" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिये अधिसूचित करती है।

[सं. 6786/फा.सं. 197-ए/95/82-आ.क. (नि.-1)]

(INCOME-TAX)

S.O. 3582.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Cathedral Relief Service, Calcutta" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 6786/F. No. 197-A/95/82-IT (AI)]

(आयकर)

का.पा. 3583—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "नेशनल कोऑपरेटिव डिवेलपमेंट कॉर्पोरेशन" को कर-निर्धारण वर्ष 1984-85 से 1987-88 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिये अधिसूचित करती है।

[सं. 6787/फा.सं. 197/163/83-आ.क. (नि.-1)]

(INCOME-TAX)

S.O. 3583.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "National Cooperative Development Corporation" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1984-85 to 1987-88.

[No. 6787/F. No. 197/163/83-IT(AI)]

(आयकर)

का.पा. 3584—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "कैंसर वेजेंट एण्ड एसोसिएशन, बम्बई" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिये अधिसूचित करती है।

[सं. 6788/फा.सं. 197/212/85-आ.क. (नि.-1)]

(INCOME-TAX)

S.O. 3584.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Cancer Patients' Aid Association, Bombay" for the purpose of the said section for the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 6788/F. No. 197/212/85-II(AI)]

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1986 :

(आयकर)

का.पा. 3585—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "कलकत्ता ज़ोरोस्ट्रियन स्री मण्डल" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिये अधिसूचित करती है।

[सं. 6802/फा.सं. 197/4/86-आ.क. (नि.-1)]

New Delhi, the 14th July, 1986
(INCOME-TAX)

S.O. 3585.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Calcutta Zoroastrian Sree Mandal" for the purpose of the said section for the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 6802/F. No. 197/4/86-IT (AI)]

(आयकर)

का.पा. 3586—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "श्री रंगम श्रीमद अन्दावन पेरिया श्रीरंगम" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिये अधिसूचित करती है।

[सं. 6803/फा.सं. 197/32/84-आ.क. (नि. 1)]

(INCOME-TAX)

S.O. 3586.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Srirangam Srimad Andavan Periasaramam Srirangam" for the purpose of the said section for the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 6803/F. No. 197/32/84-IT (AI)]

(आयकर)

का.पा. 3587—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "श्रीवासनवसी श्री अक्षर पुरुषोत्तम संस्था ट्रस्ट" को कर-निर्धारण-वर्ष 1987-88 से 1989-90 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिये अधिसूचित करती है।

[सं. 6804/फा.सं. 197/132/86-आ.क. (नि. 1)]

(INCOME-TAX)

S.O. 3587.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sechasanvasi Sri Akashar Purushottam Sanstha Trust" for the purpose of the said section for the assessment years 1987-88 to 1989-90.

[No. 6804/F. No. 197/132/86-IT (AI)]

(आयकर)

का.पा. 3588—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "श्री जयराम भाई स्वायर्षी पीठान (बाहर को) चैरिटेबल ट्रस्ट" को

कर निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1986-87 के अंतर्गत धाने वाली धबधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 6805/फा. सं. 197/112/82-घा. क. (नि. 1)]

(INCOME-TAX)

S.O. 3588.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Shree Jairambhai Dayabhai Chauhan (Bytco) Charitable Trust" for the purpose of the said section for the assessment years 1985-86 to 1986-87.

[No. 6805/F. No. 197-A/112/82-IT (AI)]

का. घा. 3589:—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23 ग) के उपखण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "भार. सी. डायोसिस आफ पलायमकोट्टै" को कर-निर्धारण वर्ष 1983-84 के अंतर्गत धाने वाली धबधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 6806/फा. सं. 197/114/86-घा. क. (नि. 1)]

S.O. 3589.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "R. C. Diocoos of Palayamkottai" for the purpose of the said section for the assessment year 1983-84.

[No. 6806/F. No. 197/114/86-IT (AI)]

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1986

का. घा. 3590:—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "अरुलमिगु हृदयकमलनाथ स्वामी मन्दिर, वलीवालम" को कर-निर्धारण वर्ष 1984-85 से 1986-87 तक के अंतर्गत धाने वाली धबधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 6829/फा. सं. 197/107/84-घा. क. (नि. 1)]

New Delhi, the 28th July, 1986

S.O. 3590.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Arulmigu Hirudayakamalanatha Swami Temple, Valivalam" for the purpose of the said section for the assessment years 1984-85 to 1986-87.

[No. 6829/F. No. 197/107/84-IT (AI)]

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1986

का. घा. 3591:—आयकर अधिनियम 1961, (1961 का 43) की धारा 80 छ की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, "अरुलमिगु मरियामन्न विनयागर मन्दिर" सुलाक्कल, कोयम्बतूर को समस्त तमिलनाडू राज्य में विख्यात सार्वजनिक पूजास्थल के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 6832/फा. सं. 176/47/86-घा. क. (नि. 1)]

New Delhi, the 1st August, 1986

S.O. 3591.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 80-G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies, "Arulmigu Mariammam Vinayagar Temple" at Sulakkal, Coimbatore to be a place of public worship of renown throughout the State of Tamil Nadu.

[No. 6832/F. No. 176/47/86-IT (AI)]

का. घा. 3592:—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ,

"मिर्जा अम्बारी तथा पारसी अजुमन, जामनगर" को कर, निर्धारण वर्ष 1986-87 से 1988-89 के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 6834/फा. सं. 197/1/86-घा. क. (नि. 1)]

S.O. 3592.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Mirza Agiari and Parsi Anjuman, Jamnagar" for the purpose of the said clause for the assessment years 1986-87 to 1988-89.

[No. 6834/F. No. 197/1/86-IT (AI)]

का. घा. 3593:—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ "एरुलमिगु पशुपतिस्वरर तिरुक्कोविल पांडानालूर" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 6835/फा. सं. 197/48/84-घा. क. (नि. 1)]

S.O. 3593.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies, "Arulmigu Pasupatheeswarar Tirukkovil, Pandanalur" for the purpose of the said section for the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 6835/F. No. 197/48/84-IT (AI)]

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1986

आयकर

का. घा. 3594:—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80-छ की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "श्री सक्मी नरसिंह नवनीत कुन्ना मंदिर, नंगानलूर, मद्रास को समस्त तमिलनाडू राज्य में विख्यात सार्वजनिक पूजा स्थल के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 6839/फा. सं. 176/5/86-घा. क. (नि. 1)]

INCOME-TAX

New Delhi, the 4th August, 1986

S.O. 3594.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 80-G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sree Lakshmi Narasimha Navaneetha Krishna Temple" at Nanganallur, Madras to be a place of public worship of renown throughout the State of Tamil Nadu.

[No. 6839/F. No. 176/5/86-IT (AI)]

आयकर

का. घा. 3595:—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 80-छ की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, "पलायम श्री महा गणपति मन्दिर" पलायम त्रिवेन्द्रम को समस्त केरल राज्य में विख्यात सार्वजनिक पूजा स्थल के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 6840/फा. सं. 176/8/86-घा. क. (नि. 1)]

INCOME-TAX

S.O. 3595.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 80-G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies, "Palayam Sree Maha Ganapathy Temple" Palayam Trivandram to be a place of public worship of renown throughout the State of Kerala.

[No. 6840/F. No. 176/8/86-IT (AI)]

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1986

(आय-कर)

का.भा. 3596.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "धनसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अन्य संरक्षित वर्ग के कर्मचारियों की कल्याण संस्था का प्रजिल भारतीय संघ (रजि.)" को कर निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 के लिये अधिसूचित करती है।

[सं. 6841/फा.सं. 197/166/85-आ.क. (नि.-I)]

New Delhi, the 4th August, 1986

(INCOME-TAX)

S.O. 3596.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "All India Federation of Scheduled Castes, Tribes, Backward and Minorities Employees Welfare Association (Regd.)" for the purpose of the said clause for the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 6841/F. No. 197/166/85-IT(AI)]

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1986

आयकर

का.भा. 3597.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "डिवीन लाइट स्कूल फार द ब्लाइण्ड ट्रस्ट" को कर-निर्धारण वर्ष 1983-84 से 1986-87 के लिये अधिसूचित करती है।

[सं. 6869/फा.सं. 197/130/86-आ.क. (नि.-I)]

New Delhi, the 14th August, 1986

(INCOME-TAX)

S.O. 3597.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Divine Light School for the Blind Trust" for the purpose of the said clause for the assessment years 1983-84 to 1986-87.

[No. 6869/F. No. 197/130/86-IT(AI)]

का.भा. 3598.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80-छ की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "श्री सूर्यनारायण देवस्थान" मारोली, मंगलूर को समस्त कर्नाटक राज्य में विद्यमान सार्वजनिक पूजा स्थल के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 6870/फा. सं. 176/51/84-आ. क. (नि-1)]

INCOME-TAX

S.O. 3598.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 80-G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies, "Sri Suryanarayana Devasthanam", Maroli, Mangalore to be a place of public worship of renown throughout the state of Karnataka.

[No. 6870/F. No. 176/51/84-IT (AI)]

का. भा. 3599.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80 छ की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, "धनसूचित

सुब्रामणियास्वामी मन्दिर, कुमारवयालूर" त्रिचि जिला को उक्त खण्ड के प्रयोजन के लिए ऐतिहासिक महत्व का स्थान अधिसूचित करती है।

[सं. 6871/फा. सं. 176/44/83-आ. क. (नि.-1)]

S.O. 3599.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 80-G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies, "Arulmighu Subramaniaswamy Temple, Kumaravayalur" Trichy Distt. to be of historic importance for the purpose of the said clause.

[No. 6871/F. No. 176/44/83-IT (AI)]

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1986

आयकर

का.भा. 3600.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, "सोसाइटी फार प्रमोशन आफ वेस्ट लैंड्स डेवलपमेंट" को कर-निर्धारण वर्ष 1987-88 से 1989-90 के लिये अधिसूचित करती है।

[सं. 6874/फा.सं. 197/150/86-आ.क. (नि.-I)]

New Delhi, the 21st August, 1986

(INCOME-TAX)

S.O. 3600.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Society for Promotion of Waste-lands Development" for the purpose of the said clause for the assessment years 1987-88 to 1989-90.

[No. 6874/F. No. 197/150/86-IT(AI)]

आयकर

का.भा. 3601.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, "लाल बहादुर शास्त्री नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 के लिये अधिसूचित करती है।

[सं. 6876/फा.सं. 197/57/84-आ. (क.नि.-I)]

(INCOME-TAX)

S.O. 3601.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Lal Bahadur Shastri National Memorial Trust" for the purpose of the said clause for the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 6876/F. No. 197/57/84-IT(AI)]

का. भा. 3602.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "द इण्डियन जिल्सी बक्स कैथोलिक ट्रस्ट" को कर-निर्धारण वर्ष 1986-86 से 1986-87 के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 6878/फा. सं. 197/77/88 आ. क. (नि.1)]

S.O. 3602.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies, "The Indian Gypsy Works Fellowship Trust" for the purpose of the said clause for the assessment years 1985-86 and 1986-87.

[No. 6875/F. No. 197/77/85-IT (AI)]

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1986

का. भा. 3603 :—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, "श्री सोमनाथ ट्रस्ट" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 6883/फा. सं. 197-क/279/82-आ.क. (नि.1)]

कै. के. त्रिपाठी, उप सचिव

New Delhi, the 25th August, 1986

S.O. 3603.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Shree Somanath Trust" for the purpose of the said clause for the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 6883/F. No. 197-A/279/82-IT (AI)]

K. K. TRIPATHI, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1986

आयकर

का. भा. 3604 :—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, "सोसायटी आफ दि सिस्टर्ज आफ दि बिवाइन सेवियर्स," मंजालुमूडु" को कर-निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1986-87 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 6898/फा. सं. 197/181/83-आ. क. (नि.-1)]

New Delhi, the 8th September, 1986

(INCOME-TAX)

S.O. 3604.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Society of the Sisters of the Divine Saviour, Manjalamoodu" for the purpose of the said clause for the assessment years 1982-83 to 1986-87.

[No. 6898/F. No. 197/181/83-IT (AI)]

का. भा. 3605 :—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, "जी आदय जगद्गुरु शंकराचार्य श्री महासामस्थान गोकर्ण ट्रस्ट" को कर-निर्धारण वर्ष 1984-85 से 1986-87 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 6899/फा. सं. 197/122/84-आ.क. (नि.-1)]

S.O. 3605.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sree Adya Jagadguru Shankaracharya Shree Mahasamasthana Gokarna Trust" for the purpose of the said clause for the assessment years 1984-85 to 1986-87.

[No. 6899/F. No. 197/122/84-IT (AI)]

का. भा. 3606 :—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, "द बिबर्न सोसायटी आफ दि फ्रांजिस्केन सिस्टर्ज आफ मेरी

को कर-निर्धारण वर्ष 1983-84 से 1986-87 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 6900/फा. सं. 197/49/84-आ. क. (नि.-1)]

रोशन सहाय, अवर सचिव

S.O. 3606.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Bombay Society of the Franciscan Sisters of Mary" for the purpose of the said clause for the assessment years 1983-84 to 1986-87.

[No. 6900/F. No. 197/49/84-IT (AI)]

ROSHAN SAHAY, Under Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1986

आयकर

का. भा. 3607 :—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घट के परन्तुक के खण्ड (इ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि., बम्बई को इसकी गृह बचत योजना स्कीम और ऋण से सम्बन्धित जमा स्कीम को उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[फा. सं. 414/104/84-आ. क. (वा.)]

एस. राजगुरु, अवर सचिव

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 18th July, 1986

INCOME-TAX

S.O. 3607.—In exercise of the powers conferred by clause (e) of proviso to Section 269SS of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies Housing Development Finance Corporation Limited, Bombay in respect of its Home Savings Plan Scheme and Loan Linked Deposit Scheme for the purpose of the said section.

[F. No. 414/104/84-IT(INV)]

S. RAJGURU, Under Secy.

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 1986

सं. 449/86-सीमा शुल्क

का. भा. 3608 :—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ राज्य क्षेत्र गोवा, पद्मन और वीर के गोवा जिले में कुडियम को शत-प्रतिशत गिर्यारोहण एकक स्थापित करने के प्रयोजनों के लिए मण्डार स्टेशन घोषित करता है।

[फा. सं. 474/28/86-सीमा शुल्क-7]

एम. मायकल, अवर सचिव

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

New Delhi, the 13th October, 1986

No. 449/86-CUSTOMS

S.O. 3608.—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby declares Kundiam in District Goa in the Union territory of Goa, Daman and Diu to be a warehousing station for the purposes of setting up of hundred per-cent export oriented units.

[F. No. 474/28/86-CUS. VII]

M. MICHAEL, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

(बैंकिंग प्रभाग)

(मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 1986

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1986

आदेश

क्र. आ. 3609.—भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1984 (1984 का 18) की धारा 6 की उपधारा (4) के साथ पठित उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (iv) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री जगदीश जोशी प्रबंध निदेशक, महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगम, बम्बई को श्री एम. पी. उपासनी के स्थान पर 9 अप्रैल, 1989 तक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का निदेशक नामित करती है। यह आदेश तत्काल लागू हो जाएगा।

[सं. एफ. 7/19/85-बी. प्रो. - 1]

एम. एस. सीथरामन, अवर सचिव

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 3rd October, 1986

S.O. 3609.—In pursuance of sub-clause (iv) of clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (4), of section 6 of the Industrial Development Bank of India Act, 1964 (18 of 1964), the Central Government hereby nominates Shri Jagdish Joshi, Managing Director, Maharashtra State Financial Corporation, Bombay as Director of the Industrial Development Bank of India with immediate effect upto 9-4-89 vice Shri S. P. Upasani.

[No. F. 7/19/85-BO.I]

M. S. SEETHARAMAN, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 18th October, 1986

CORRIGENDA

S.O. 3610.—In the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 2656 dated the 2nd August, 1986 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 2nd August, 1986, at pages 3006 to 3007 and 3009 to 3011—

- (a) at page 3006 (Annexure-I), in clause 4, in the Table
 - (i) against S. No. (iv), for the entry under the heading "Requirement", for "specified 3 per cent" read "specified + 3 per cent",
 - (ii) against S. No. (v), for the entry under the heading "Requirement" for "Not below 30C" read "not below 30°C".
 - (iii) against clause 5, for the heading "Odour Eastness Test" read "Colour Fastness Test".
- (b) at page 3007 (ANNEXURE IV), in clause 6, (Weight per 10 litres) in line 2, for "50%" read "±5%".
- (c) at page 3099 (SCHEDULE-II), against clause (b) Sub-clause (i) for "Emulsion Points" read "Emulsion Paints."
- (d) at page 3010 (SCHEDULE-II), against clause (b) sub-clause (ii) against S. No. 7, for "Water Repellancy" read "water repellancy".
- (e) at page 3011 (SCHEDULE-III), in line 2 of para 1.3, for "1 litre" read "10 litre".

[F. No. 6(5)/85-EI&FP]

N. S. HARIHARAN, Director

क्र. आ. 3611.—श्री अमरीक सिंह, 27/35, द्वितीय मंजिल पंजाबी बाग, नई दिल्ली को एक डायमलर बेन्ज, टाइप 240-डी, कार का आयात करने के लिए 1,14,000/- रु. मूल्य का एक सीमा शुल्क निकासी परमिट सं. पी/जे/3072318 दिनांक 25-5-84 दिया गया था। आवेदक ने उक्त सीमा शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन दिया है कि मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट अस्थानस्थ/खो गया है। अतः यह भी बताया गया है कि मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट को किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं कराया गया था तथा इस प्रकार सीमा शुल्क निकासी परमिट के मूल्य का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया है।

2. अपने तर्कों के समर्थन में लाइसेंस धारक ने उचित व्यापिक प्राधिकारी के सम्मुख विद्युत शपथ लेकर एक शपथपत्र दाखिल किया है जिसमें तदनुसार, संसुष्ट है कि आवेदक द्वारा मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट सं. पी/जे/3072318, दिनांक 25-5-84 खो गया है। समय-समय पर यथा संशोधित आयात (निर्यात) आदेश, 1955, दिनांक 7-12-1955 की उप-धारा 9 (गग) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अमरीक सिंह को जारी उक्त मूल सीमा-शुल्क निकासी परमिट सं. पी./जे./3072318, दिनांक 25-5-84 का एतद्वारा रद्द किया जाता है।

3. पार्टी को सीमा-शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति को अलग से जारी किया जा रहा है।

[क्र. सं. ए/ए. एच/558/83-84/बी. एल. एस/1590]

एन. एस. कृष्णामूर्ति, उप मुख्य नियंत्रक]

आयात-निर्यात

(Office of the Chief Controller of Imports & Exports)

New Delhi, the 30th September, 1986

ORDER

S.O. 3611.—Mr. Amrik Singh, 27/35, 2nd floor, Punjabi Bagh, New Delhi has granted Customs Clearance Permit No. P/J/3072318 dt. 25-5-84 for Rs. 1,14,000 only for import of One No. Daimler Benz. type 240-D car. The applicant has applied for issue of Duplicate Copy of the above mentioned Customs Clearance Permit on the ground that the original CCP has been misplaced/lost. It has further been stated that the original CCP was not registered with any Customs authority and as such the value of the CCP has not been utilised at all.

2 In support of his contention, the licensee has filed an affidavit duly sworn before appropriate judicial authority. I am accordingly satisfied that the original CCP No. P/J/3072318 dt. 25-5-84 has been lost by the applicant. In exercise of the powers conferred under Sub-Clause 9(cc) of the Import (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended from time to time, the said original CCP No. P/J/3072318 dt. 25-5-84 issued to Mr. Amrik Singh is hereby cancelled.

3. A duplicate copy of the Customs Clearance Permit is being issued to the party separately.

[F. No. A/AH/558/83-84/BLS/1590]

N. S. KRISHNAMURTHY, Dy. Chief Controller of Imports & Exports.

For Chief Controller of Imports & Exports.

(संयुक्त मुख्य निर्यातक, आयात-निर्यात कार्यालय)

(केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र)

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1986

निरस्त-आदेश

का. बा. 3612.—सर्वश्री इंडियन कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड, सी. 73, सेक्टर-II, नोएडा, जिला-गाजियाबाद (उ. प्र.) को इलेक्ट्रॉनिकी टाईपराईटर के उत्पादन हेतु दिनांक 31-3-86 को, 18,88,000 रु. की राशि का आयात लाइसेंस न. पी/एस/1969599 जारी किया गया था।

आवेदक फर्म इस कथन के समर्थन में अब एक शपथ-पत्र, आयात-निर्यात की कार्यविधि पुस्तिका 1985-88 के पैरा 85-87 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। कि सीमाशुल्क प्रयोजन काफी जो कि ए. एम. 86 में जारी लाइसेंस सं. पी/एस/1969599 दिनांक 31-3-86 रुपये 18,88,000 के अन्तर्गत जारी की गई थी किसी भी पक्ष पर पंजीकृत किए गए तथा बिना उपयोग किए ही गुम हो गई है/ अस्थानस्थ हो गई है।

मैं सन्तुष्ट हूँ कि आयात लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन काफी हो गई है/ अस्थानस्थ हो गई है।

अतः आयात : व्यापार नियंत्रण आदेश 1955 दि. 7-12-55 (यथा संशोधित) की पी/एस में प्रदत्त अधिकारियों का प्रयोग करते हुए मैं उपरोक्त लाइसेंस संख्या 1969599 दि. 31-3-86 रु. 18,88,000 की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन काफी को निरस्त करने का आदेश देता हूँ।

आवेदक की प्रार्थना पर अब आयात-निर्यात की कार्यविधि-पुस्तिका 1985-88 के पैरा 85-87 के अनुसार उक्त लाइसेंस सं. पी/एस/1969599 दि. 31-3-86 रु. 18,88,000 सीमाशुल्क प्रयोजन काफी की अनुलिपि (डुप्लीकेट काफी) जारी करने पर विचार किया जाएगा।

[सं. -यू. पी./सप्ली 171/ए. एम.-86/ए. यू. आई./सीएलए./2153]

(Office of the Joint Chief Controller of Imports & Exports)
(Central Licensing Area)

New Delhi, the 17th July, 1986

CANCELLATION ORDER

S.O. 3612.—M/s. Indian Communication Nett Work Ltd., B-73, Sector-II, Noida District Ghaziabad (UP) were granted import licence No. P/S/1969599 dated 31st March, 1986 for Rs. 18,88,000 for manufacturing of electronic typewriters.

The applicant has filed an affidavit as required under para 85-87 of hand book of Import Export Procedure 85—88 policy wherein they have stated that custom purpose copy of the licence No. P/S/1969599 dated 31st March, 1986 for Rs. 18,88,000 issued for the period of AM. 86 has lost/misplaced without having been registered at any port and utilised at all.

I am satisfied that the custom purpose copy of the licence have been lost/misplaced.

In exercise of the power conferred on me under sub-clause-9(d) of the Import Trade Control order, 1955 dated 7th December, 1955 as amended upto date, the said custom purpose copy of the licence No. P/S/1969599 dated 31st March, 1986 for Rs. 18,88,000 is hereby cancelled.

The applicant is now being issued duplicate custom purpose copy of Import licence No. P/S/1969599 dated 31st March, 1986 for Rs. 18,88,000 in accordance with the provision of para 85—87 of the hand book of Import & Export Procedure 85—88.

[F. No. UP/Suppl./71/AM.86/AU.I/CLA/2153]

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1986

निरस्त आदेश

का. बा. 3613.—सर्वश्री हिन्दुस्तान वायरस लिमिटेड, 267-268, सेक्टर-24 फरीदाबाद (हरियाणा) को स्टील वायर का उत्पादन करने के लिए आयात लाइसेंस न. पी./डी/2240819 दिनांक 27-9-85 रुपये 27,10,000 जारी किया गया था।

आवेदक ने आयात नियंत्रण क्रियाविधि पुस्तिका 85-88 के पैरा 85-87 के अन्तर्गत बांछित शपथपत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि लाइसेंस सं. पी/डी/2240819 दि. 27-9-85 रु. 27,10,000 जो कि अप्रैल-मार्च 1986 में जारी किया गया था कि एक्सचेंज परपज प्रतिनिधि बिना उपयोग किये ही कहीं खो गई है/ अस्थानस्थ हो गई है तथा वह किसी भी पक्ष पर पंजीकृत भी नहीं कारवाई गई थी।

मैं सन्तुष्ट हूँ कि उक्त आयात लाइसेंस की मूल एक्सचेंज परपज काफी खो गई है/अस्थानस्थ हो गई है।

अतः आयात-व्यापार नियंत्रण आदेश 1955 दि. 7-12-55 (यथा संशोधित) की धारा में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं उपरोक्त लाइसेंस सं. पी/डी/2240819 दि. 27-9-85 रु. 27,10,000 की मूल एक्सचेंज परपज काफी को निरस्त करने का आदेश देता हूँ।

आवेदक की प्रार्थना पर अब आयात-निर्यात की कार्यविधि-पुस्तिका 1985-88 के पैरा 85/87 के अनुसार उक्त लाइसेंस सं. पी/डी/2240819 दि. 27-9-85 रु. 27,10,000 की एक्सचेंज परपज काफी की अनुलिपि (डुप्लीकेट काफी) जारी करने पर विचार किया जायेगा।

[सं. डी. जी. टी. डी./सप्ली/151/एम. 86/ए. यू. सी. एल. ए./2234]

New Delhi, the 29th July, 1986

CANCELLATION ORDER

S.O. 3613.—M/s. Hindustan Wires Ltd., 267-268 Sector-24 Faridabad (Haryana) were granted import licence No. P/D/2240819 dt. 27-9-85 for Rs. 27,10,000 for manufacturing of Steel Wire.

The applicant has filed an affidavit as required under para 85—87 of Hand Book of Import Export Procedure 85—88 policy wherein they have Stated that Exchange purpose copy of the licence No. P/D/2240819 dt. 27-9-85 for Rs. 27,10,000 issued for the period of AM. 86 has lost/misplaced without having been registered at any port and utilised at all.

I am satisfied that the Exchange purpose copy of the licence have been lost/misplaced.

In exercise of the power conferred on me under Sub-Clause-9(d) of the Import Trade Control-Order, 1955 dt. 7-12-1955 as amended upto date, the said Exchange purpose copy of the licence No. P/D/2240819 dt. 27-9-85 for Rs. 27,10,000 is hereby cancelled.

The applicant is now being issued duplicate Exchange purpose copy of import licence No. P/D/2240819 dt. 27-9-85 for Rs. 27,10,000 in accordance with the provision of para 85—87 of the Hand Book of Import & Export procedure 85—88.

[F. No. DGTD/Suppl/151/AM.86/AU.I-CLA-2209]

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1986

निरस्त आदेश

का.आ. 2614—मैं श्री सुन्दर सिंह एवं कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, 36, के.एम.जी.टी. रोड, सोनीपत को रेफ्रिजरेटर मशीनों के आयात हेतु दिनांक 14-4-85 को 2,73,900/- रु. को राशि का आयात लाइसेंस सं. पी/डी/2240614 जारी किया गया था।

आवेदक ने सूचित किया है कि ए.एम. 85 के निर्यात दिनांक 14-4-85 को 2,73,900/- रुपये के आयात लाइसेंस सं. पी.डी.-2240614 को कस्टम प्रयोजन प्रतिलिपि बिना उपयोग बिना निर्यात पत्र पर पंजीकरण किये गये हैं / अस्थानस्थ हो गई है। उन्होंने लाइसेंस सं. पी./डी./2240614 दिनांक 10-4-85 को एम.एम. प्रयोजन प्रतिलिपि निरस्त करने के लिए भी प्रस्तुत की है।

मैं समुचित हूँ कि उक्त आयात लाइसेंस का नून पंजीकरण प्रयोजन कारी हो गई है/अस्थानस्थ हो गई है।

अतः आयात-रिपार्त नियंत्रण आदेश 1955 दि. 7-12-55 (या संशोधित) की धारा में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं उक्त लाइसेंस सं. पी/डी/2240614 दि. 10-4-85 रु. 2,73,900/- को दोनों प्रतिलिपियों को निरस्त करने का आदेश देता हूँ।

[फाइल सं. डी. जी. टी. डी/अवर्ज/440/एम.एम. 85/ए. यू. I/पी. एन. ए./2463]

आर. के. धवन, उप मुख्य निर्यात आयात-नियंत्रण,
उक्त समुचित मुख्य निर्यात, आयात-नियंत्रण

New Delhi, the 5th August, 1986

CANCELLATION ORDER

S.O. 3614.—M/s. Sunder Singh & Co. Pvt. 36, K.M.G.T. Road Sonapat was granted import licence No. P/D/2240614 dt. 14-4-85 for Rs. 2,73,000 for manufacturing of refrigeration machinery.

The applicant has reported that Custom purpose copy of the licence No. P/D/2240614 dt. 14-4-85 for Rs. 273000 issued for the period of AM. 85 has lost/misplaced without having been registered at any port and utilised at all. They have also surrendered the Exchange control copy of lic. No. P/D/2240614 dt. 10-4-85 for cancellation.

I am satisfied that the Custom purpose copy of the licence have been lost/misplaced.

In exercise of the power conferred on me under sub-clause 9(d) of the Import Trade Control Order, 1955 dt. 7-12-55 as amended upto date, both copies of the licence No. P/D/2240614 dt. 10-4-85 for Rs. 2,73,900 is hereby cancelled.

[F. No. DGTD/Others/440/AM. 85/AU.I/CLA-2463]

Dr. R. K. DHAWAN, Dy. Chief Controller of
Imports & Exports.
for Jt. Chief Controller of Imports & Exports.

घोषणा मंत्रालय

(सांख्यिकी विभाग)

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 1986

का. आ. 3615.—इस विभाग की दिनांक 1 अगस्त, 1986 को अधिसूचना संख्या एम-12011/1/86-समन्वय का अधिकार आदेशों के तहत हुए भारतीय सांख्यिकी संस्था अधिनियम, 1959 के खंड 8 (1) के 914 GI/86—2

अन्तर्गत वर्ष 1987-88 के लिए स्थापित सामान की अवधि सरकार को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 31 मार्च, 1987 तक बढ़ाई गई है।

[संख्या एम-12011/1/86-समन्वय]

जोगिन्दर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PLANNING

(Department of Statistics)

New Delhi, the 1st October, 1986

S. O. 3615.—In partial modification of this Department's Notification No. M-12011/1/86-Coord. dated 1-8-1986, the Committee set up under Section 8(1) of the Indian Statistical Institute Act, 1959 for the year 1987-88 has been given extension of time up to 31st March, 1987 for submitting its report to the Government.

[No. M-12011/1/86-Coord]

JOGINDER SINGH, Under Secy.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 1986

का.आ. 3616.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधिसूचना का.आ.सं. 2135 तारीख 1-5-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का रूपना दायम घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और दाने, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और दाने उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में केन्द्रीय उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित, होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस दायम में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

वायर वेड व ऐनोड वेड बिछाने के लिए

राज्य — गुजरात जिला — मेहसाना तालुका :—कड़ी

गांव	सर्वे नं.	हे.	घा.र.	सं.
बलाबडी	248	0	01	20
	250	0	01	25

[सं. O-120 16/43/85—डी एन जी—डी-4]

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 1st October, 1986

S.O. 3616.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. 2135 dated 1-5-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM WIRE BED & ANODE BED

State : Gujarat District : Mehsana Taluka; Kadi

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centi-are
Vlavadi	248	0	01	20
	250	0	01	25

[No. O-12016/43/85-ONG-D4]

का.आ. 3617—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में ऐल. डब्ल्यू. ऐ. ई./ऐल-12 से मेहसाना-12 (एन-4) तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रयोग द्वारा बिजली बनाने का अधिकार है।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी ज़रूरतों को बिजली के प्रयोग के लिए एतदुपलब्ध भूमि में उपयोग का अधिकार प्रदान करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार प्रदान करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

अतः कि उक्त भूमि में निम्नलिखित कोई व्यक्ति, उस भूमि के लोके पाइपलाइन बिछाने के लिए आशेष सख्त प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाव, सड़क/रुल रोड, बसोडरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर करसकेगा।

और ऐसा आशेष करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितः यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की माध्यम से।

अनुसूची

ऐल. डब्ल्यू. ऐ. ई./ऐल-12 से मेहसाना-12 (एन-4) तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : चाणसा

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
धनोदरदा	518	00	09	24
	519	00	09	24
	521	00	3	48
	520	00	08	16

[सं. O-12016/164/86-ओ एन जी-डी-4]

S.O. 3617.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from LWAE/L-12 to Mehsana-12/L-4 in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FROM LWAE/L-12 TO MEHSANA 12 (L-4)

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Chansma

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centi-are
Danadarada	518	0	09	24
	519	0	09	24
	521	0	3	48
	520	0	08	16

[No. O-12016/164/85-ONG-D4]

का.आ. 3618—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का-50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस प्रशासन की अधिसूचना का.आ.सं. 2293 तारीख 2-6-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिश्चित भूमियों के उपयोग के अधिकार को प्राप्त लाइन को बिछाने के लिए प्रदान करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः समस्त प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद् द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, वायवा के प्रहसन की इस सारीख की निहित नहीं होगी।

अनुसूची

एस.एन. सी.टी.एफ. कम-जी.जी.एल. से स्टीम बिन्दु तक पाइपलाइन बिछाने के पलए।

राज्य : गुजरात

जिला व तालुका : मेहसाणा

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	छात्रे	सेन्टीयर
कसलपुरा	818	0	16	80
	862	0	04	20
	861	0	03	72
	860	0	03	60
	869	0	03	84
	893	0	05	52
	852	0	01	68
	851	0	02	58
	850	0	03	90

[सं. O-12016/94/86-ओ एन जो-डॉ-4]

S.O. 3618.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. 2293 dated 2-6-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM SS.CTF-CUM-GGS TO STEAM POINT.

State : Gujarat

District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	Acres	Centiare
Kasalpura	818	0	16	80
	862	0	04	20
	861	0	03	72
	860	0	03	60
	869	0	03	84
	893	0	05	52
	852	0	01	68
	851	0	02	58
	850	0	03	90

[No. O-12016/94/85-ONJ-D4]

का.भा. 3618 :—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एन.उम.ए.ई./एन-12 से मेहसाणा 12(एन-4) तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस उपयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसा त.द.ओं का बिछाई त.रागत के लिए एतद्गुणवत् अनुसूची में वर्गीकृत भूमि में उचित का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों (का प्रयोग करते हुए सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्रयास एतद् द्वारा घोषित किया है।

यद्यपि कि उक्त भूमि में हितरक्ष कोई व्यक्ति, उन भूमि त.नाके पाइपलाइन बिछाने के लिए आशेष सभन प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और वेबसाइट प्रमाण सफरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख 9 21 दिनांक त.रागत कर सकेगा।

और ऐसा आशेष करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या यह चाहता है कि उक्त भूमि त.रागत कर से हो या किसी विधि व्यवसाय की मार्फत।

अनुसूची

एन.उम.ए.ई./एन-12 से मेहसाणा-12 (एन-4) तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाणा तालुका : तालुका

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	छात्रे	सेन्टीयर
लजवा	416	0	09	98
	415/2	0	00	36
	418/1	0	02	52
	428	0	03	40
	429	0	09	24
	430	0	08	40
	436	0	04	08
	435	0	07	20

[सं. O-12016/163/86-ओएनजी-डी-4]

S.O. 3619.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from LWAE/L-12 to Mehsana-12 (L-4) in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from LWAE/L-12 To Mehsana-12 (L-4)

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Chansama

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Lanawa	416	0	09	96
	415/2	0	00	36
	418/1	0	02	52
	428	0	05	40
	429	0	09	24
	430	0	08	40
	436	0	04	08
	435	0	07	20

[No. O-12016/163/86-ONG-D4]

का. आ. २६१०.—यः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एन. के.-९ से एन. के. जी.जी.एस.-I तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस अयोग द्वारा विछर्द जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपायद अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, १९६२ (१९६२ का ५०) की धारा ३ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बतते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के लिये पाइपलाइन बिछाने के लिए आवेदन सजम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-९ को इस अधिसूचना की तारीख से २१ दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आशय करने वाला हर व्यक्ति जितनियतः यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवस्थायो को माफ़ें।

अनुसूची

एन. के.-९ से एन.के.जी.जी.एस.-I तक पाइपलाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : विरमगांव

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आरे.	सेंटीयर
भाटारीया	8	0	13	68
	137	0	37	20
	139/2	0	16	08
	139/1	0	04	56
	140/3	0	08	64
	140/6	0	13	20
	142/2	0	12	24
	142/1	0	06	60
कार्ट ट्रेक		0	04	80
	62/2	0	07	80
	63	0	13	08
	60/5	0	03	60
	60/4	0	05	28
	60/2	0	05	88
	60/1	0	03	96
	59/2	0	00	72
	71/3/ए	0	02	64
	71/2/ए	0	01	80
	71/1/ए	0	05	40
	72/2	0	07	80
	72/3	0	07	20

[सं. O-12016/162/86-ओएनजी-बं. 4]

S.O. 3620.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from NK-9 to NK GGS-I in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares the intention to acquire the right of user therein;

Provide that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline NK-9 to N.K. GGS I.

State : Gujarat	District : Ahmedabad	Taluk : Viramga m		
Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Bhataria	8	0	13	68
	137	0	37	20
	139/2	0	16	08
	139/1	0	04	65

Village	Survey No	Hectare	Area	Centiare
	140/3	0	08	64
	140/6	0	13	20
	142/2	0	12	24
	142/1	0	06	60
	Cart track	0	04	80
	62/2	0	07	80
	63	0	13	08
	60/5	0	03	60
	60/4	0	05	28
	60/2	0	05	88
	60/1	0	03	96
	59/2	0	00	72
	71/3/A	0	02	64
	71/2A	0	01	80
	71/1/A	0	05	40
	72/2	0	07	80
	72/3	0	07	20

[No. O-12016/162/86-DNG-D4]

का. घा. 3621.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का धर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम, और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. घा. सं. 2287 तारीख 28-5-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना प्राश्य घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन के इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एस. बी. ए. डी. में सोमासज जोजोएन।

राज्य—गुजरात जिला ब तालुका मेहसाणा

गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टर	एयार्ड	सेंटीघर
	182	0	12	12
	181/1	0	21	60
कोचवा	180	0	08	40
	193	0	21	00
	175	0	11	40
	172 } 174 }	0	25	92
	149	0	10	44
	147	0	02	64
	148	0	11	16

[सं. O-12016/92/86-ओएनजी-डी 4]

S.O. 3621.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S. O. 2287 dated 28-5-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipe Line from SBAD to SOB GSR II

State : Gujarat Dist & Taluka Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Kochva	182	0	12	12
	181/1	0	21	60
	180	0	08	40
	193	0	21	00
	175	0	11	40
	172 } 174 }	0	25	92
	149	0	10	44
	147	0	02	64
	148	0	11	16

[No. O-12016/92/86-ONG-D4]

का. घा. 3621.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का धर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. घा. सं. 1826 तारीख 26-5-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना प्राश्य घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवर्तक शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी माघाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

कूप नं. जे. धार. जे. से झालोरा-9 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य: गुजरात जिला: मेहसाणा तालुका: कदी

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटियर
करसनपुरा	30	0	10	95
	28	0	07	75
	29	0	09	00

[सं. O-12016/32/84-पी एन सी-डी 4]

S.O. 3622.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy & Deptt. of Petroleum & Natural Gas S.O. 1826 dated 26-5-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipe line from well No. JRJ Jhalora-9.

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi.

Village	Survey No.	Hectare	Ars	Centiare
Karsanpura	30	0	10	95
	28	0	06	75
	29	0	09	00

[No. O-12016/32/84-ONG-D4]

का. धा. 3623.—जतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (यूजर में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की अधिसूचना का. धा. सं. 2286 तारीख 26-5-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अर्पण घोषित कर दिया था।

और जतः समस्त प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 कं. उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिर्णय किया है।

अतः, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवर्तक शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवर्तक शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी माघाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एस. एम. डी.ए. से जीओएस-I

राज्य--गुजरात जिला--महस सावुका--होसोड ,

गांव	प्लॉट नं.	हेक्टेयर	एआरडी	सेंटियर
वासनेर	काटे ट्रेक	0	03	90
	186	0	16	90
	195/ए,	0	15	60
	195/बी	0	11	70
	452	0	15	60
	193	0	13	00
	192	0	07	80
	548	0	06	50
	547	0	07	15
	541	0	23	40
	528	0	11	70
	527	0	15	60
	523 }			
	522 }	0	08	45
	520	0	05	85
	509	0	06	50
	508	0	27	95
	507	0	06	50

[सं. O-12016/91/86-पीएनसी-डी 4]

S.O. 3623.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S. O. 2286 dated 28-5-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPE LINE FROM SMDA TO GGS I

State : Gujarat Dist. : Bharguch Taluka : Hansof

Village	Block No.	Hectare	Acre	Centiare
Walner	Cart track	0	03	90
	196	0	16	90
	195/A	0	15	60
	195/B	0	11	70
	452	0	15	60
	193	0	13	00
	192	0	07	80
	548	0	06	50
	547	0	07	15
	541	0	23	40
	528	0	11	70
	527			
	523	0	15	60
	522	0	08	45
	520	0	05	35
	509	0	06	50
	508	0	27	95
	507	0	06	50

[No. O-12016/91/86-ONG—D4]

का. प्र. 3624 :- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की अधिसूचना का. प्र. स. 2291 तारीख 28-5-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न भूमियों में निम्नलिखित भूमियों के उपयोग के अधिकार की पाइप लाइन को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना अधिकार घोषित कर दिया था;

और यतः सक्षम अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 2 दी;

और अतः, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न भूमियों में निम्नलिखित भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विधिकरण किया है;

अतः, यतः उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न भूमियों में निम्नलिखित उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है;

और अतः उपधारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की दृष्टि तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

सोसायटी--9 से डब्लू. डब्लू. टी. पी.

राज्य--गुजरात जिला व तालुका--मेहसाणा

गांव	सं. नं.,	हेक्टेयर	एकर	सेंटिअर
	158	0	05	64
	198	0	08	12
जगुदन ,	160	0	17	16
	180	0	17	64
	179	0	02	16
	165	0	00	72
	166	0	06	36
	167	0	08	64
	168	0	03	48
	169	0	17	40
	171	0	11	88

[स. O-12016/85/86/ओएनजी-4]

S.O. 3624.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S. O. 2291 dated 28-5-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to require the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipe Line from SOB-9 to WWTP

State : Gujarat Dist & Taluka : Mehsana.

Village	Survey No	Hectare	Acre	Centiare
Jagudan	158	0	05	64
	198	0	08	12
	160	0	17	16
	180	0	17	64
	179	0	02	16
	165	0	00	72
	166	0	06	36
	167	0	08	64
	168	0	03	48
	169	0	17	40
	171	0	11	88

[No. O-12016/85/86-ONG-D4]

का. भा. 3625.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. भा. सं. 2116 तारीख 15-5-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अतः, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए, एतद्वारा अर्जित किया जाता है;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एस. ओ. बी.-3 से एस.ई.आई.-73 तक पाइप बिछाने के लिए
राज्य: गुजरात जिला: मेहसाणा

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	घार.	सेंटीयर
सोभासन	84	0	08	76

[सं. O-12016/63/86-ओएनजी-बी 4]

S.O. 3625.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S. O. 2116 dated 15-5-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section right of user in the said lands shall instead of vesting in right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from SOB-3 to SEY-73

State : Gujarat

District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hectares	Ares	Centiare
Sobhasan	84	0	08	76

[No. O-12016/63/86-ONG-D-4]

का. भा. 3626.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय की अधिसूचना का. भा. सं. 3187 तारीख 27-9-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अतः, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

कसोल--96 से के-194 से बी.जी. एस-4 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य: गुजरात

जिला: मेहसाणा

तालुका: कनोन

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	घार.	सेंटीयर
कसोल	257/143	0	13	35
	257/142	0	09	00
काटेंद्र		0	00	65
	257/140	0	13	50
	252/98	0	17	82
	252/69	0	19	50
	252/100	0	12	45
	252/39	0	08	34
	252/37	0	08	81
	252/34	0	08	19

ह/ सक्षम अधिकारी

[सं. O-12016/101/84-ओएनजी-बी 4]

पी. के. चण्डीयाजी, उक्त अधिकारी

S.O. 3626.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S. O. 3187 dated 27-9-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Use in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Kalol-96 to K-194 to GGS-4.

State : Gujarat	District : Mehsana	Taluka - Kalol		
Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Kalol	252/143	0	13	35
	252/142	0	09	00
	Cart track	0	00	65
	252/140	0	13	50
	952/98	0	17	82
	252/61	0	10	50
	252/100	0	12	45
	252/39	0	08	34
	252/37	0	08	81
	25 /34	0	03	19

[No. O-12/16/10/84-ONG—D4]

Sd.— Competent Authority
P. K. RAJAGOPALAM, Desk Officer

परिवहन विभाग

(जन-भूतन परिवहन विभाग)

(नौवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 1986

का.आ. 3627 :—राष्ट्रीय पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 353 छ की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व नौवहन और परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2322, तारीख 20 जून, 1979 को अधिकांत करते हुए, नीचे दी सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को उक्त धारा के प्रयोजन के लिए नियुक्त करती है जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट तटस्थानी प्रविष्टी में विनिर्दिष्ट पतनों, महापत्तों पर या भारत के सामुद्रिक क्षेत्र में पोतों के संबंध में उक्त धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग भी करेंगे, अर्थात्:—
914 GI/86—3

सारणी

अधिकारी का नाम पतनों, महापत्तों या भारत के सामुद्रिक क्षेत्र का नाम

1.	2.
1. निदेशक (समुद्री विभाग) या कप्तानता उसकी अनुपस्थिति में, उपनिदेशक (समुद्री), महापत्तन, कलकत्ता	
2. प्रबंधक (समुद्री गंतिका), महा- इन्दिया पत्तन, इन्दिया	
3. उपसंयोजक या उसकी अनुपस्थिति में, सूचना में बन्दरगाह मास्टर या दोनों की अनुपस्थिति में, निदेशक (प्रत्यक्ष नियंत्रण) महापत्तन, मुम्बई	
4. उपसंयोजक, महापत्तन	सभी अन्य महापत्तन
5. तटस्थ अधिनियम, 1978 (1978 का 30) की धारा 3 के अन्तर्गत तटस्थ के अधिकार स्वतंत्रता: इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए :—	
(क) "महापत्तन" पर का वही अर्थ है जो उसे भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) में दिया गया है ;	
(ख) "भारत का सामुद्रिक क्षेत्र" पर का वही अर्थ है जो उसे तटस्थ अधिनियम, 1978 (1978 का 30) में दिया गया है ।	

[न. एन डब्ल्यू/5-एम एन आर (3)/83-एम एन सुदर्शन सिविल, अवसर सचिव]

MINISTRY OF TRANSPORT

(Department of Surface Transport)

New Delhi, the 3rd October, 1986

S.O. 3627.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 356G of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) and in supersession of the notification of the Government of India in the then Ministry of Shipping and Transport No. S.O. 2322 dated the 20th June, 1979, the Central Government hereby appoints officers specified in column (1) of the Table below for the purposes of the said section who shall also exercise the powers under the said section in respect of ships in ports, major ports or maritime zone of India, specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, namely :—

TABLE

Name of the Officer	Name of the port, major port or maritime zone of India
1	2

1. The Director (Marine Department) or in his absence, the Deputy Director (Marine), Major Port of Calcutta.
2. The Manager (Marine Operations), Major Port of Haldia.

3. The Deputy Conservator or in Bombay his absence, the Harbour Master or in the absence of both, the Director (Pollution Control), Major Port of Bombay.
4. The Deputy Conservator, Major All other major ports Ports.
5. Officers of Coast Guard within Maritime Zone of India the meaning of section 3 of the Coast Guard Act, 1978 (30 of 1978).

Explanation :—For the purposes of this notification,—

- (a) the expression "major port" has the same meaning as assigned to it in the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908);
- (b) the expression "Maritime Zone of India" has the same meaning as assigned to it in the Coast Guard Act, 1978 (30 of 1978).

[F. No. SW/5-MSR(3)/83-MA]

S. SYNGHAL, Under Secy.

अन्य संज्ञाएँ

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 1986

का. आ. 3628.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार नियुक्त पब्लिक कमिशनर, हैदराबाद के प्रत्यक्षतन्त्र से संबंधित नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकारण, हैदराबाद के पंचांग को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 24-9-86 को प्राप्त हुआ था।

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 6th October, 1986

S.O. 3628.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Hyderabad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Nuclear Fuel Complex, Hyderabad and their workmen, which was received by the Central Government on the 24th September, 1986.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL)
AT HYDERABAD

PRESENT :

Industrial Dispute No. 23 of 1985

BETWEEN

The Workman of Nuclear Fuel Complex, Hyderabad.

AND

The Management of Nuclear Fuel Complex, Hyderabad.

APPEARANCES :

Sri C. Venkata Krishna, Advocate—for the Workmen.
Sri K. V. Subba Rao, Additional Government Standing Counsel—for the Management.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its Order No. L-42025(3)/83-D, II(B)/D.V, dated 16th April, 1985 referred the following dispute under Sections 10(2A), (1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the employers in relation to the management of Nuclear Fuel Complex, Hyderabad and their workman to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Nuclear Fuel Complex, P.O. ECIL, Hyderabad-500762 in removing Sri M. Prakasam, Ex-Tradesman (B) SMP with effect from 25th October, 1978 is justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

This reference was registered as Industrial Dispute No. 23 of 1985 and notices were issued to parties.

2. The claims statement filed by one M. Prakasam, ex-Tradesman NFC against the Management Chief Executive N.F.C., Hyderabad questioning his removal from service with effect from 25th October, 1978. It is mentioned by him that he was appointed as Tradesman on 17th November, 1972 and served in Nuclear Fuel Complex without any bad remarks and he was made permanent also. While so, to his surprise the Management served with suspension order on 4th January, 1977 under Standing Order 41.3, they served a charge sheet impugning misconduct and also supplied him with other enclosures. According to him in the charge sheet it is alleged that he slapped the Canteen Supervisor Sri K. Rama Krishna in front of several employees and canteen boys and the same resulted an enquiry being contemplated against him. It is his case that the enquiry was conducted without observing the principles of natural justice and no opportunity was given to him. It is also mentioned that the domestic enquiry was conducted as contemplated as an empty formality and thus it vitiated the principles of natural justice. He questioned the said enquiry conducted against him on various grounds as mentioned in the affidavit filed in this industrial dispute. Therefore he held that the Enquiry Officer was prejudiced and influenced and he violated all the principles of natural justice while conducting the enquiry and he was finally led to termination. He also mentioned that he filed a Writ Petition No. 7855/82 and which is enclosed to the petition wherein it was directed that the matter should be referred to the Tribunal as there is remedy upon him and thus the matter be disposed of in accordance with law and justice should be done to him.

4. He also filed an additional petition stating that till the date of suspension on 4th January, 1977 there was not even a single complaint against him at any point of time and he was attending to duties and discharging diligently to the satisfaction of the superiors. The petitioner denied the charge that he obstructed Sri K. Rama Krishna, Canteen Supervisor while he was discharging his duties or that he slapped him etc. as false and baseless. According to him he was not allowed to take the assistance of K. V. Rao, Store Keeper to defend himself. It is his case that his witness examined for the Management by name Venkateshachalam was not present at the time of incident and that he came later to the spot from his room after the incident is over. It is said that second witness Ram Gopi, Watchman did not see anything and the evidence of the said witness did not stand the test of scrutiny. Similarly he questioned the veracity of the third witness P. Jayaram, Assistant Security Officer stating that he was not present at the time of the incident. Finally he mentioned that the complaint was examined who tried to identify and he was paraded. He also mentioned that the Scientific Officer was planted witness and he did not know anything.

4. He mentioned that the Enquiry Officer submitted a report on 19th May, 1978 and he was held guilty for misconduct. Despite his representation on 17th September, 1978 the Chief Executive who is appointing authority passed order of removal as per Para 43 as per Nuclear Fuel Complex Standing Orders read with B.A.F. Notification 22(1) of 1863 A.I.M. dated 3rd December, 1970 and that the impugned order is dated 25th October, 1978 and the said order is not a speaking order. Though he filed a representation to review after the matter which was rejected, he filed a Writ Petition No. 7853/82 and the matter was referred finally to Industrial Tribunal. According to him the order of removal is passed vindictively and it amounted to unfair labour practice. According to him the Standing Orders that are applicable to him are not properly considered and therefore the removal is not sustainable under law and therefore he sought for reinstatement with attendant benefits and back wages.

5. In the counter filed by Personnel Manager, Administrative Nuclear Fuel Complex by name C. G. Kulkarni. He mentioned that all the allegations made by the Petitioner against the Management were false. It is also denied that the Petitioner had unblemished career. It is their case that the charge sheet with all the required documents were supplied to him showing the details of misconduct and the Enquiry Officer conducted the enquiry as per the rules and principles of natural justice also denied. He denied the suggestion that

the Enquiry Officer submitted his report with pre-determined biased mind and loaded him guilty on the charges levelled against him. According to him the Enquiry Officer gave every reasonable opportunity to the petitioner and the findings are valid and in accordance with law. It is also mentioned that when the charges are so grave the Chief Executive felt that it is not safe to continue him in service and therefore rightly decided to remove him and the orders of removal was passed by the Deputy Chief Executive. He also mentioned that when a review petition is filed to the Chief Executive as a Appellate Authority the same were also rejected. According to him there are no valid grounds to maintain his petition and the person was properly dealt with on merits after giving him reasonable and fair opportunity regarding the misconduct and the petitioner having assaulted the Canteen Supervisor and when the same is proved beyond reasonable doubt it is argued that lesser punishment cannot be thought of in the interest of the discipline and principles of natural justice.

6. Both sides did not lead any oral evidence and the Workman marked Ext. W1 and W2 on his side by consent. The Management marked Exs. M1 to M10 by consent.

7. The admitted facts that the petitioner was an employee as Tradesman B. Caste in the Nuclear Fuel Complex. He joined service on 17th November, 1972 and continued in the said post till the date of his removal on 25th October, 1978 though he was suspended on 4th January, 1977 pending enquiry. He continued to be in service till the order of removal dated 3rd January, 1977 along with Ex. M2. According to him the order of disciplinary proceedings is dated 4th January, 1977 under Ex. W1 and it also stated that he was kept under suspension under para 41.3(1) of Nuclear Fuel Complex Standing Orders and it is signed by the Deputy Chief Executive. He was served with the charge sheet Memorandum under Ex. W2. It is mentioned in Ex. W2 dated 13th January, 1977 that as per Annexure I all the imputation of misconduct or misbehaviour were set out and the article in support of the said Annexure are mentioned in Annexure II and the list of documents were shown from Annexure III and list of witness as per Annexure IV. He was asked to submit his defence within 7 days after the receipt of the same and he should appear before the Enquiry Officer. The same is marked as Ex. W2.

8. On behalf of the Management Ex. M1 is marked containing the charge sheet as well as the Annexure I, II, III and IV and Ex. M2 is the letter of the Management showing that the delinquent received the same. He was supplied with the letter from K. Ramakrishna, Canteen Supervisor dated 3rd January, 1977 along with Ex. M2. According to him when he was speaking to the Welfare Officer regarding the incident that took place on the allegations of Sampat Dhillon regarding the quantity of rice in the lunch plate being less etc. He found that some people gathered at his counter and one person among the persons by name M. Prakasam, Tradesman pulled him and slapped him and those persons who were taking tiffin in the Canteen saw him including the duty Watchman and Sri Jayaram, A.S.O. also came to the Canteen and he narrated the same. Thus he went and reported the matter to Sri A. K. Taneja and he also identified the said person who slapped him. Ex. M3 is the appointment order of the Enquiry Officer, the charge framed against him for conducting the enquiry dated 7th February, 1977. Ex. M4 are the enquiry proceedings relating to the delinquent. They are serially numbered as from pages 9 to 77 and marked as Exs. M4. Ex. M5 is the Enquiry Officer report in serially numbered from pages 78 to 96. Ex. M6 the Memorandum served on delinquent giving him further opportunity to make representation on the proposed penalty. It is shown from pages 97 to 99. Ex. M7 is the representation dated 17th September, 1978 by M. Prakasam. It is pages from 100 to 102. He contended that the prosecution failed to prove and establish the guilt. He also mentioned that another case filed against Anjaiah for serious mis conduct was subsequently exonerated of the charges. According to him the Canteen Supervisor as well as the Welfare Officer and the Watchman and duty Assistant Security Officer are colluded and the enquiry officer was also biased and thus he was implicated. According to him the preponderance of evidence is in his favour and the enquiry officer had taken the view quite contrary to the same and he mentioned that the findings of the Enquiry Officer are thus biased and suffer from perversion and lack of objective assessment. He also mentioned that any accept-

ance of the said findings will be only mechanical and he also mentioned that the Deputy Chief Executive did not apply his mind to the real facts. Ex. M8 is the dismissal order dated 25th October, 1978. Ex. M9 is the appeal preferred by Sri M. Prakasam to the Chief Executive on 8th December, 1978 and he contended that the Deputy Chief Executive passed the orders of removal illegally and without jurisdiction. According to him he did not even consider the representation by him and sought for reinstatement. Ex. M10 is the final orders of the Chief Executive dated 16th March, 1979 where he upheld the departmental enquiry conducted as well as the action of removal done by the Deputy Chief Executive and he held that the petitioner was involved in a very serious and grave misconduct that affected the discipline in the plant and deserved the said punishment and did not require interference from his side. Though these are photostat copies, by consent they are marked.

9. The allegation against the petitioner is that on 3rd March, 1977 he obstructed K. Ramakrishna, Canteen Supervisor and that he pulled the said Supervisor and slapped him when he was attending to the complaint received from some other workman and thus he upheld in the manner unbecoming of Government servant. Of course that the petitioner comes within the definition of 'workman' under the established definition of Industrial Disputes Act is not questioned. The petitioner was paid sustenance allowance with effect from 4-1-1977 till the date of removal on 25-10-1978 as seen from the written argument. Of course he also admitted that the Annexure I to IV were served him along with letter dated 3-1-1977 which is the result of the complaint given by K. Ramakrishna and that he acknowledged the same which was served on 17-1-1977. The enquiry officer is one Ahur Walia as per Annexure IV to support Annexure I. Three witnesses were mentioned, but ultimately 9 witnesses were examined in chief and they were also cross examined. Thus it is argued that a conscious effort on the part of the Department was made to secure the guilt of the worker in one manner or other. Acts of misconduct as per Nuclear Fuel Complex Standing Orders [C.C.S. (conduct) Rules] are Clause 8 and 26 i.e. Clause 8 reads as follows: assaulting or intimidating any workman/supervisor/officer of the NFC arising out of employment. Clause 26 reads as follows: Carrying lethal weapons concealed or otherwise fighting, causing or attempting to cause bodily injury to another employee/person, drunkenness, bootlegging or other acts which violate the common law or intimidating any person or employee of NFC within the premises. General Clause I would show every Government servant shall at all times do nothing unbecoming of the Government servant. So the management lead evidence to show that obstruction caused to K. Ramakrishna, Canteen Supervisor by Prakasam is nothing but obstructing the public servant in discharging of his duties and when he was slapped on his face it amounted to assaulting him and it constitute a serious misconduct. Actually the petitioner was assisted by Assisting Officer. He wanted first one K. V. Rao to assist him in his application dated 10-3-1977 since he was not the fellow employee he was asked to me another person. Then Prakasam by his letter dated 15-3-1977 instated that he could be only given service of K.V. Rao and finally after further correspondence. The assistance of K. V. Rao was granted and on 30-6-1977 C. Venkatachallam prosecuting witness was examined along with Ramgopi. But the cross examination of Ram Gopi could not be completed on that day. At that stage the delinquent sought for change of Enquiry Officer and the same was rejected by the Administrative Officer. All this is found in Ex. M5 which are enquiry officer's proceedings. On the next date of adjournment i.e. 24-11-1977 the evidence of Sri K. Sree Ramakrishna was recorded in the presence of Presenting Officer. The defence witnesses were recorded. There afterwards the defence cited 9 witnesses and finally defence witnesses were examined from 11-1-1978 and the recording of evidence was over by 8th February, 1978. The Enquiry Officer considered the deposition of the prosecution witnesses including the complainant and the defence witnesses D.W1 to D.W9.

10. The case of the prosecution is that on 3-1-1977 the Petitioner obstructed K. Sreeramakrishna Canteen Supervisor and he pulled the said Supervisor and slapped him when he was attending to the complaint received from some workmen and behaved in a manner unbecoming of the Government servant. The case of the defence is that the said delinquent did not go to the Canteen on that day. It must be noted at

the outset when the Management cited three names in Annexure IV and subsequently when Plant Manager was also examined with the complainant as they were vitally connected with the incident, the Assisting Officer as well as the delinquent did not object for the same. Moreover the charge is based upon the very complaint of K. Sreeramakrishna and the date when the complaint is given to him no objection could have been raised during the course of enquiry also for his examination. Though Venkatachalam was not an eye-witness to the occurrence when he was informed about the incident of slapping to the Canteen Supervisor, he went out of his room to the Canteen where the Canteen Supervisor narrated to him the entire facts and further he also told him that the person belong to S.M.P. as he was wearing uniform that the letters M.P. and S.M.P. Then with the Assistance of Canteen boys and Assistant Security Officer Jayaram, the entire incident was narrated to Sri Taneja the Plant Manager and Mr. Prakasham was identified as the person who slapped the Canteen Supervisor. The Canteen boys also identified Prakasham as the correct person who was involved in the incident and from the identification parade conducted by Sri Taneja it was established that it was found that Prakasham was present who was the person guilty. The non-examination of the Canteen boys which is not taken as objection during the domestic enquiry by the Delinquent cannot be considered as a serious omission in these proceedings. The witnesses need not be multiplied. The Plant Manager in his capacity as Plant Manager was well within his limits to conduct such an identification parade to know the culprit and infact the evidence of Ram Gopi could confirm that there is slapping incident in the Canteen. But the Enquiry Officer did not rely too much upon the evidence of Ram Gopi as he was not cross examined and moreover as he was also absent for being cross examined from duty for several months. But the Assistant Security Officer Jayaram mentioned that the Canteen Supervisor told him that he did not know the name of the delinquent but gave him the particulars and he was wearing the uniform with S.M.P. marking and he also informed him and Taneja that he reported these facts. Now when there are 2,000 employees in Nuclear Fuel Complex establishment who visited the Canteen for their breakfast, lunch, tea etc. It is highly impossible to remember the names of the employees who go to the Canteen for their requirements. So the injured person mentioned that he did not know the name of Prakasham. It did not mean that the delinquent subsequently traced cannot be connected with the incident properly by circumstantial reliable evidence moreover he was properly identified as the culprit by the injured person as well as those who have seen it. The Assistant Security Officer further mentioned how Ramakrishna when asked to identify the person in the presence of Taneja mentioned that in the first group of people including the Canteen boys and the Watchmen the culprit was not there and when the second group of people were called in along with Prakasham, he was shown as the person who entered the room. The injured person Ramakrishna pointed out to him this prakasam as the person who slapped him.

11. The incident happened in the four walls of the canteen and therefore it cannot be argued that there is no daily maintenance regarding the incident. It is purely an administrative matter which is taken up by the Departmental Officials including the Plant Manager. Of course the evidence of Canteen Supervisor would show that 8 coupons belonging to the Petitioner were surrendered to the Canteen during the lunch time between 1.00 to 1.30 P.M. It would also show that Prakasham who was also physically present in the Canteen at the time of incident as a circumstance. It is only connecting link to prove that Prakasham was present in the lunch time at Canteen apart from direct evidence and identification of Prakasham by the injured person as well as others. Infact Prakasham was wearing uniform bearing that of S.M.P. which is clear indication that he belonged to the Special Material Plant and when incidentally stressed and when Taneja immediately acted upon the reported slapping in the Plant premises and when an identification is conducted in the presence of A.S.O. as well as Canteen boys and Venkatachala Murthy, it cannot be said that such an identification was not in accordance with law. When the injured person complaint to the Plant Manager regarding the slapping by the Petitioner, it cannot be said that the injured person and Taneja who conducted identification should not be examined on the ground that their names were not found in the

Annexure. The very fact the injured gave a complaint which is supplied to him and that Taneja conducted identification Parade clinchingly among 2,000 workers of Nuclear Fuel Complex, in his own way which is fair to prove or to find or spot out the person, it cannot be said that Taneja was partial or biased in holding the fact pending enquiry. The argument of the workmen that there is no credible evidence to prove the presence of the accused workman in the Canteen on the alleged date of incident is not correct. According to the workman he borrowed uniform from one of his colleagues and he tried to explain that he had kept the soiled uniform. When he questioned whether he was identified by the Canteen Supervisor and Canteen Boys as the man who slapped the Canteen Supervisor on that day, the delinquent officer stated that the said Ramakrishna and two canteen boys did not say anything in front of him. Infact Ramakrishna answered that Prakasham spent S.M.P. coupons issued from a book issued to Prakasham. Further Prakasham admitted that Welfare Officer was there in the room at that time and when Ramakrishna and two canteen boys identified him and he could not say how many coupons he had in his book at that time. He admitted that lunch time for him is between 1.00 and 1.30 P.M. According to him there were five people with him when he took lunch and he mentioned the names of Narayana, Anand, Sambasiva Rao, Pandu and one Dayashanker as the persons were examined and he examined them as witness for him. The injured person also described that he observed the person who slapped him was having the uniform MP/ SMP with small pox marks and he also asserted that he could recognise by seeing his face though his dress is changed. The injured expressed that he had no enmity with him. When he was asked and questioned how he mentioned in the complaint that Sri Prakasham T/B S.M.P. had pulled and slapped him and asked him to elaborate the injured answered that he was pulled by his shoulder and slapped him. He was further asked what prevented him from catching him after slapping, he explained that in confusion he had no occasion to catch but he could only give a complaint regarding this to the Management. He asserted slapping took place between 1.15 to 1.30 p.m. which is the lunch hour prescribed for S.M.P. employees. When he was asked whether he remembered to have seen this accused government servant on this particular day, the injured answered that he saw him only while he was slapping. He clearly narrated he saw the person who slapped him and also noted the initials on his uniform and was able to recognise him by his pox marks on face. Thus it is the evidence of the injured Ramakrishna is clinching and direct and fresh and it cannot be said that there was any flaw in identification of Prakasham as the person involved in the occurrence. On the basis of defence evidence of D.W.1 to D.W.9 which is also varying it cannot be said that Prakasham did not take his lunch in the canteen on that day but he had taken lunch at S.M.P. Office itself from theiffin dhaba along with his friends and that he did not go to the place of incident in the canteen. The answers given by the defence witnesses is only to negative the incident but it is not their case that they were present at the Canteen and that no such incident took place in their presence. The witnesses were examined in defence to show that the delinquent was with them elsewhere at the time of incident. So the entire story set up in the defence with one voice as a trumped up story can be seen as artificial and unnatural. The injury aspect namely that he was slapped in the canteen while he was discharging his duties and that he identified the person whose coupons were also used to show that he attended the canteen and he had his lunch in canteen and further that he was also seen by the persons when he was slapped and he was rightly identified by injured immediately when identification parade was conducted would show that the complainant had no specific motive to depose in a choosian way against the delinquent. Therefore all the defence evidence of D.W. 1 to D.W. 9 will not wash out the actual incident as if it was false case set up and that he was implicated. I have gone through the entire evidence of witnesses and also enquiry proceedings of the witnesses under Exs. M4 and M5 the enquiry report and I find that once the injured identified the delinquent immediately after the incident in the identification parade conducted by Taneja, it cannot be brushed aside easily by trumped up defence evidence that the delinquent person was not present at the Canteen as narrated by D.W. 1 to D.W. 9. The coupons issued to the delin-

quent as well as presence of officers at the time of identification by the injured spotting the delinquent in the presence of Taneja which is natural and which is also done immediately as narrated by them to show that the defence version is not the real version and that the injured was speaking the correct facts as he was the affected party and no motive is attributed by the defence for Ramakrishna to spot out the delinquent as culprit. In the given circumstances I hold that the charge being grave and he was rightly ordered to be terminated by the Deputy Chief Executive and on appeal also the Chief Executive confirmed the same as seen from Exs. M8 and M10 respectively. It cannot be said that the charge is vague and that there is no direct evidence of witness about the incident. It cannot be said that the Deputy Chief Executive had no power to remove the delinquent and that he acted illegally beyond his jurisdiction. The very Standing Order which are quoted by Prakasam would show that the management complied with all the requisite formalities and based upon evidence held that Prakasam voluntarily obstructed Sri Ramakrishna, Canteen Supervisor, while he was discharging his duties on 3-1-1977 and further slapped him while he was attending to a complaint received from some of the workmen. Therefore I do not find any inconsistency or irregularity or illegality in the proceedings, and the quantum of sentence passed in the given circumstances.

12. On a careful consideration of the entire material, I hold that the action of the Management of Nuclear Fuel Complex, P.O. ECIL, Hyderabad 500762 in removing Shri M. Pakasham, Ex-Tradesman (B), SMP with effect from 25-10-1978 is justified and that he is not entitled to any relief.

Award is passed accordingly.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him, Corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 2nd day of September, 1986.

Appendix of Evidence

Witnesses Examined for
the workmen:

Witnesses Examined for the Management:

NIL

NIL

Documents marked for the Workmen :

- Ex. W1 By consent.—Order No. Ref. NFC/PA. V/20/87, dt. 4-1-77 issued to M. Prakasam by the Dy. Chief Executive, Nuclear Fuel Complex.
- Ex. W2 By consent.—Memorandum Ref. NFC/PA. V/20/223, dt. 13-1-77 issued to M. Prakasam, Tradesman (B) by the Dy. Chief Executive, Nuclear Fuel Complex.

Documents marked for the Management :

- Ex. M1 By consent.—Photostat copy of the Memorandum of charge sheet dt. 13-1-77 issued to M. Prakasam by the Deputy Chief Executive, Nuclear Fuel Complex.
- Ex. M2 By consent.—Photostat copy of the acknowledgement letter dt. 21-1-77 from M. Prakasam to the Deputy Chief Executive, N.F.C., Hyderabad.
- Ex. M3 By consent.—Photostat copy of the appointment order dt. 7-2-77 of H.S. Ahluwalia, SO(SE), TPP as enquiry officer to enquire into the charge framed against M. Prakasam.
- Ex. M4 By consent.—Photostat copy of the enquiry proceedings against M. Prakasam.
- Ex. M5 By consent.—Photostat copy of the enquiry officer report against M. Prakasam.
- Ex. M6 By consent.—Photostat copy of the Memorandum dt. 6-8-78 addressed to M. Prakasam by the Dy. Chief Executive, N.F.C. Hyderabad.

Ex. M7 By consent.—Photostat copy of the representation dt. 17-9-78 made by M. Prakasam to the Dy. Chief Executive, Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad.

Ex. M8 By consent.—Photostat copy of the dismissal order dt. 25-10-78 issued to M. Prakasam by the Dy. Chief Executive, NFC., Hyderabad.

Ex. M9 By consent.—Photostat copy of the appeal dt. 6-12-78 made by M. Prakasam to the Chief Executive N.F.C., Hyderabad.

Ex. M10 By consent.—Photostat copy of the order of the Appellate authority dt. 16-3-79.

Sarma: 12-9-86

J. VENUGOPALA RAO, Industrial Tribunal

[No. L-42025/37/83-D. II(B)]

HARI SINGH, Desk Officer

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 1986

का.आ. 3629.—लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान तथा क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि नियम, 1978 के नियम 3 के प्रति लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान तथा क्रोम अयस्क खान श्रम संज्ञाव्यय कल्याण निधि अधिनियम, 1976 (1976 का 61) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 25-1-86 के 296 से 298 पृष्ठों पर प्रकाशित भारत सरकार के श्रम संज्ञाव्यय की दिनांक 15 जनवरी, 1986 की अधिसूचना का. आ. सं. 261 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में क्रमिक 11, 20 और 21 पर की गई प्रविष्टी के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

11. कल्याण आयुक्त,
सेक्टर चैलेंजर ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट,
कान्कुरगची, मानिकताला, मेन रोड,
कलकत्ता-700054
20. श्री के. एच. मनी, ज्योसोसिकल एडवाइजर,
मिनरल डिवेलपमेंट बोर्ड, दख्खन बिन्डिंग,
11, टाजस्टाय मार्ग, नई दिल्ली।
21. श्री ए. खालिक, जॉब पर्सनल मैनेजर,
मेनरल मिनरल डेवेलपमेंट कांसोरेजिया,
खनीज भवन, मल्ल टाक, हैदराबाद-28.

[सं. यू.-23011/3/84-कल्याण-2]

New Delhi, the 6th October, 1986

S.O. 3629.—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Iron Ore, Manganese Ore and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund Act, 1976 (61 of 1976) read with rule 3 of the Iron Ore, Manganese Ore and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund Rules, 1978, the Central Government hereby makes the following amendment to the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 261 dated 15th January, 1986 published at pages 296 to 298 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 25th January, 1986, namely:—

In the said notification for entries against serial numbers 11, 20 and 21 the following shall be substituted, namely:—

11. Welfare Commissioner,
Labour Welfare Training Institute,
Kankurgachi, Manicktala, Main Road,
Calcutta-700054

20. Shri K.S. Mani, Geological Adviser,
Mineral Development Board,
Vandhana Building,
11, Tolosty Marg, New Delhi.
21. Shri A. Khalique, Chief Personnel Manager,
National Mineral Development Corporation,
Khanij Bhawan, Masab Tank, Hyderabad-28.

[No. U. 23011[3]84-W. II]

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 1986

का.आ. 3630.—केंद्रीय सरकार, चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1973 के नियम 3 के उप-नियम (2) और नियम 4 के उप-नियम (1) के साथ पठित चूना और डोलोमाइट श्रम खान कल्याण निधि 1972 (1972 का 62) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए मध्य प्रदेश राज्य के लिए निम्नलिखित सदस्यों वाली एक सलाहकार समिति का गठन करती है :-

1. श्रम मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार, : अध्यक्ष
भोपाल।
2. चूना पत्थर और डोलोमाइट खान कल्याण : उपाध्यक्ष
आयुक्त, श्रम कल्याण संगठन, 41, नरसिंह
रोड, जबलपुर।
3. क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कल्याण), जबलपुर। : केंद्रीय सरकार के प्रति-
निधि सदस्य।
4. डा. राकेश कुमार सिंह, सदस्य, विज्ञान सभा, : सदस्य
जिला जंजौर, बिलासपुर।
5. श्री बी. एन. जैन, मुख्य कार्यकारी, सैवरा } : नियोजकों के प्रतिनिधि
सामेंट, रायपुर।
6. श्री बी. बी. भादुरी, मुख्य अव्ययक (जान) }
बिलाई।
7. श्री जे. आर. डूबे, अध्यक्ष, चूना मजदूर } : कर्मचारियों के प्रतिनिधि
कमिटी, कांडीौर।
8. श्री मंगल प्रसाद शुक्ला, सचिव, सेहारा नर्सिंग }
वर्कर्स यूनियन, नर्सिंग, सेहारा।
9. श्रीमती मंजु राय, सदस्य, विज्ञान सभा, सेहारा : महिला प्रतिनिधि
जबलपुर।
10. कल्याण प्रशासक, चूना पत्थर और डोलोमाइट : उच्च
खान, श्रम कल्याण संगठन, जबलपुर।

2. चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1973 के नियम 18 के अनुसार, केंद्रीय सरकार, मध्य प्रदेश के लिए चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि के लिए जबलपुर का राज्य सलाहकार समिति का मुख्यालय निश्चित करती है।

[प्रख्या-यू. 19012/3/85-वल्क-II (सो)]

एच. एच. भस्मा, जवर सचिव

New Delhi, the 9th October, 1986

S.O. 3630.—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972 (62 of 1972) read with sub-rule (2) of rule 3 and sub-rule (1) of rule 4 of the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Rules, 1973, the Central Government hereby constitutes an Advisory Committee for the State of Madhya Pradesh consisting of the following members for a period of three years from the date of publication of this notification, namely :—

1. Labour Minister,
Government of Madhya Pradesh,
Bhopal. —Chairman

2. The Limestone and Dolomite
Mines Welfare Commissioner,
Labour Welfare Organisation,
44, Narbada Road, Jabalpur —Vice-Chairman

3. Regional Labour Commissioner,
(Central), Jabalpur. —Member repre-
senting Central
Government

4. Dr. Rakesh Kumar Singh,
Member, Legislative Assembly,
District Janjgir, Bilaspur. —Member

5. Shri B. L. Jain,
Chief Executive,
Century Cement, Raipur. }
6. Shri B. B. Bhaduri,
Chief Superintendent (Mines),
Bhilai. } —Employers
representatives

7. Shri J. R. Dube, President,
Chuna Mazdoor Congress,
Kymore. }
8. Shri Ganga Prasad Shukla,
Secretary, Central Mines
Workers Union, Nandini,
District Durg. } —Employees'
representatives

9. Shrimati Manju Rai,
Member, Legislative Assembly,
Sehara, Jabalpur. —Woman
representative

10. Welfare Administrator
in the Limestone and
Dolomite Mines Labour,
Welfare Organisation,
Jabalpur. —Secretary.

2. In accordance with rule 18 of the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Rules, 1973, the Central Government hereby fixes Jabalpur as the headquarters of the State Advisory Committee for Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund for Madhya Pradesh.

[No. U-19012[3]85-W.II(C)]

S. S. BHALLA, Under Secy.

नई दिल्ली 7 अक्टूबर, 1986

का. आ. 3631.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसार में, केंद्रीय सरकार, भारत औद्योगिक कोल लि. की बेनेडीह कोलियरी के प्रबंधन से संबंधित औद्योगिक विवाद और उनके कर्मचारियों के बीच अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 1, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केंद्रीय सरकार को 23-9-1986 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 7th October, 1986

S.O. 3631.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Benedih Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 23rd September, 1986.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under Sec. 10(1)(d), of the
Industrial Disputes Act, 1947
Reference No. 45 of 1983

PARTIES :

Employers in relation to the management of Benedih
Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Ltd.

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Shri I. N. Sinha, Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri B. Joshi, Advocate.

For the Workmen—Shri S. Bose, Secretary, Rashtriya
Colliery Mazdoor Sangh.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal
Dhanbad, the 15th September, 1986

AWARD

The present reference arises out of Order No. L-20012
(81)/83-D.IIIA, dated the 18th June, 1983, passed by the
Central Government in respect of an industrial dispute bet-
ween the parties mentioned above. The subject matter of
the dispute has been specified in the schedule to the said
order and the said schedule runs as follows :—

“Whether the action of the management of Benedih
Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited
Dhanbad in not granting clerical Grade II to Shri
Kunwar Jyoti Dutta, Clerk is justified? If not, to
what relief is the workman entitled and from what
date?”

2. The dispute has been settled out of Court. A memo-
randum of settlement has been filed in Court. I have gone
through the terms of settlement and I find them quite fair
and reasonable. There is no reason why an award should
not be made on the terms and conditions laid down in the
memorandum of settlement. I accept it and make an award
accordingly. The memorandum of settlement shall form
part of the award.

3. Let a copy of this award be sent to the Ministry as
required under section 15 of the Industrial Disputes Act,
1947.

Dated : 15-9-86.

I. N. SINHA, Presiding Officer

[No. L-20012/81/83-D.III(A)]

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL
GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL I,
DHANBAD

Ref. No. 45/83

Employers in relation to the management of Block-II
Area Office,

AND

Their workmen.

PETITION OF COMPROMISE

The humble petition on behalf of the parties above
named most respectfully herewith :—

1. That, without prejudice to the respective contention of
the parties, the dispute referred by notification No. L-20012
(81)/83-D.III(A) dated 18th June, 1983 for adjudication
has been settled on the following terms :—

TERMS OF SETTLEMENT

(a) That, Shri K. J. Dutta shall be given Grade-II
(Clerical) with effect from 1st December, 1982.

(b) That, it was agreed that the concerned workman
shall be given notional seniority from 1st October,
1979.

2. That, in view of the aforesaid settlement there remains
nothing to be adjudicated.

Under the facts and circumstances stated above, the
Hon'ble Tribunal will be graciously pleased to accept the
terms of the settlement as fair and proper and will be pleased
to pass the Award in terms of the settlement.

For the workmen

B. N. Yadav

Witness :—

1. Sd/- Illegible

2. Sd/- Illegible

For the Employers

1. Sd/-

2. Sd/-

3. Sd/-

Presiding Officer

Central Govt. Industrial Tribunal No. I.
Dhanbad

का. बा. 3632:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
(1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार न्यूसेलेक्टेड
धोरी कोलियरी में सी. सी. लि., डाक धोरी लि. गिरिदिह के प्रबंधकों
से संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच अन्तर्गत में निम्नलिखित
औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिनियम नं. 2, धनबाद
के पचाई को प्रकाशित करता है, जो केन्द्रीय सरकार को 29-9-86 को
प्राप्त हुआ था।

S.O. 3632.—In pursuance of section 17 of the Industrial
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government
hereby publishes the following award of the Central Gov-
ernment Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad, in the indus-
trial dispute between the employers in relation to the man-
agement of New Selected Dhori Colliery of Central Coal-
fields Limited, P.O. Dhori, Distt. Giridih and their work-
men, which was received by the Central Government on the
23rd September, 1986.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 119 of 1985

In the matter of industrial disputes under Section 10(1)(d)
of the I.D. Act, 1947

PARTIES :

Employers in relation to the management of New Select-
ed Dhori Colliery of M/s. Central Coalfields Limi-
ted, P.O. Dhori, Distt. Giridih and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen—Shri S. Bose, Secretary,
R.C.M.S.

On behalf of the employers—Shri R. S. Murthy, Advo-
cate.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal

Dhanbad, the 17th September, 1986

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following disputes to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-24012(21)/85-D.IV(B), dated the 5th August, 1985.

SCHEDULE

"Whether the action or the management of New Selected Dhori Colliery of C.C. Ltd., P.O. Dhori, Dist. Giridih in denying reinstatement of Shri Parmeshwar Nayak, son of Shri Teklal Nayak is legal and justified? If not to what relief is the workman concerned entitled?"

In this reference the workmen have filed their W.S. Thereafter several adjournments were granted to the parties. But ultimately on 28-8-86 Shri R. S. Murthy, Advocate representing the employers filed before me memorandum of settlement. I have gone through the terms of settlement which I find that the same is fair and proper. Accordingly I accept the same and pass an Award in terms of the settlement which forms part of the Award as annexure.

Dated 17-9-1986.

I. N. SINHA, Presiding Officer
[No. L-24012/21/85-D.IV(B)]

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL NO. 2, DHANBAD

Ref. No. 119 of 1985

PARTIES :

Employers in relation to the management of New Selected Dhori Colliery of M/s. Central Coalfields Limited, P.O. Dhori, Dist. Giridih.

AND

Their workmen.

JOINT COMPROMISE PETITION OF THE EMPLOYERS
AND WORKMEN

The abovementioned employers and the workmen concerned in the above reference most respectfully beg to submit as follows :—

1. That the Management and workmen have jointly negotiated the matter covered by the above reference for the purpose of arriving at a mutual and overall settlement.

2. That as a result of the aforesaid negotiations, the Management and the workmen have come to an overall and amicable settlement on the matter on the following terms and conditions :—

(a) It is agreed that the Management shall provide employment to Sri Parameshwar Nayak, w.e.f. 15-9-1986 subject to his being found medically fit as piece rated worker in the job of Over Burden Remover/Quality Loader. The Management shall have the right to transfer him any where according to its requirements including even to any underground mine.

(b) It is agreed that the workman concerned will not be entitled to any back wages or any other benefits in regard to his past service or the intervening period.

(c) It is agreed that this is an overall settlement in respect of all the claims of the workman concerned and the sponsoring union in respect of the aforesaid reference.

3. That the employers and the workmen/union concerned consider that the aforesaid terms and conditions are fair, just and reasonable to both the parties.

In view of the above, the employers and the workman/union jointly pray that the Hon'ble Tribunal may be pleased to give an award in terms of this joint compromise petition and dispose of the reference accordingly.

(Ram Paur Tripathi)

Asstt. Secretary, R.C.M.S.

Sathara Area

for and on behalf of Union/employee

Sd/- (Illegible)

Project Officer/Agent

New Selected Dhori Colliery

Central Coalfields Ltd.

For and on behalf of employer

Sd/-

R. S. Murthy, Advocate

For Employers

Witnesses :

1. R. S. Sharma, Advocate.

28-8-86

2. Jugal Kishore Singh

का. भा. 3633.—घोषाधिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 की 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारत कोकिंग कोल लि. की, भोवरा (दक्षिण) कोलियरी के प्रबंधन से संबंध नियोक्ता और उनके कर्मचारों के बीच, अनुलग्न में निम्नलिखित घोषाधिक विवाद में केन्द्रीय सरकार घोषाधिक अधिकरण, नं. 2 धनबाद के पचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार की 19-9-1986 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 3633.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bhowra (South) Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 19th September, 1986.

(ANNEXURE)

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 46 of 1985

In the matter of industrial disputes under Section 10(1)(d)
of the I.D. Act, 1947

PARTIES :

Employers in relation to the management of Bhowra (South) Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen—Shri S. Bose, Secretary
R.C.M.S. Union.

On behalf of the employers—Shri R. S. Murthy,
Advocate.

STATE : Bihar

INDUSTRY : Coal

Dhanbad, the 12th September, 1986

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d)

of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No L-20012 (390)/84-D.III(A), dated the 26th April, 1985.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Bhowra (South) Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, P.O. Bhowra (Distt. Dhanbad) in dismissing from service Shri Dhiren Bouri, Permanent Drill Coal Loader, with effect from 7-11-1983 is justified. If not, to what relief the workmen concerned is entitled?"

In this reference both the parties filed their respective W.S. documents etc. Thereafter several adjournments were granted to the parties and ultimately on 26-8-86 both the parties appeared before me and filed a memorandum of settlement which appears to be fair and proper. Accordingly I accept the same and pass an Award in terms of the memorandum of settlement which forms part of the Award as annexure.

Dated 12-9-1986.

I. N. SINHA, Presiding Officer

[No. L-20012/390/84-D.III(A)]

A.V.S. SARMA, Desk Officer

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL
TRIBUNAL NO. 2, DHANBAD

In the matter of Reference No. 46 of 1985

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Bhowra
(S) Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited.

AND

Their workmen.

JOINT PETITION OF COMPROMISE OF MANAGEMENT AND WORKMEN

The above mentioned employers and the workmen most respectfully beg to submit this joint compromise petition.

(1) That the Management and workmen have jointly negotiated the matter covered by the aforesaid reference with a view to arriving at an overall and amicable settlement.

(2) That as a result of such negotiations, the Management and the workmen have come to an amicable and overall settlement of the matter on the following terms and conditions :—

- (a) It is agreed that the Management shall provide employment afresh to the workman concerned Sri Dhiren Bouri as under ground Miner/Loader in Bhowra (S) Colliery, subject to his being found fit physically and mentally by the Medical Board of BCCL at Jealgora.
- (b) It is agreed that the fresh employment as referred to in clause (a) above will be provided to Sri Dhiren Bouri in Bhowra (S) Colliery from the date he reports for duty after he has been declared medically fit as aforesaid.
- (c) It is agreed that since this will be purely a fresh appointment the workman concerned shall not be entitled to any other benefit with regard to his past service or otherwise.
- (d) It is agreed that this is an overall settlement in full and final settlement of all the claims of the workman concerned/union concerned representing the workman concerned arising out of the aforesaid reference.

(3) In view of the above, the Management and the workmen jointly pray that the Honble Tribunal may be pleased

914 GI/86—4

to give an award in terms of the aforesaid settlement/agreement and dispose of the reference accordingly.

Sd/-

Secretary,

R.C.M.S.,

For and on behalf of workmen.

General Manager,
Bhowra Area,
Bharat Coking Coal Limited,
P.O. Bhowra, Dist. Dhanbad
For and on behalf of employers.

Sd/-

(Dhiren Bouri)

Workman concerned

Sd/-

(Raj. S. Murthy)

Advocate,

For Employers.

Witnesses :—

1. R. S. Sharma, Advocate

2. L.T.I.

Dhanbad dated the 26th August, 1986.

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 1986

का. आ. 3634...केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया कि सूचीकोरित पत्तन न्यास, सुतीकोरित का क्षेत्र कर्मशाला के कर्मचारी अन्वेषण उन प्रसुविधाओं को प्राप्त कर रहे हैं जो भारत : कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के अधीन उपबंधित प्रसुविधाओं के समान है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 91-क के साथ पठित धारा 90 द्वारा प्रवृत्त करने पर ध्यान देकर और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 915, तारीख 19 फरवरी, 1986 के क्रम, में कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात् उपर्युक्त कारखाने को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 अक्टूबर, 1985 से 30 सितम्बर, 1987 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, अवधि के लिए छूट देती है।

2. उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात् :—

- (1) उक्त कारखाने को नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था (जिसे हममें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियाँ ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी ;
- (2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या हम निमित प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पधारी :—
 - (1) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि के लिए दी गई किसी विवरणी की प्रविष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिए ; या
 - (2) यह अभिलिखित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं ; या

- (3) यह अभिनियमित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी नियोजक, द्वारा की गई उन प्रमुखियों को, जो ऐसी प्रमुखियां हैं जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, निकट और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है, या नहीं; या
- (4) यह अभिनियमित करने के प्रयोजन लिए उसे अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं;

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा :-

- (क) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या
- (ख) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के अधिभोग के कारखाने स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भार साधक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के सन्दाय से संबंधित ऐसे लेखाबहियां और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे या;
- (ग) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक को, उसके अभिरक्षा या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति को जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास विश्वास करने का व्यक्तिगत कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या
- (घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबहियां या अन्य दस्तावेज की तकल करना या उससे उद्धरण लेना।

[संख्या एस 38014/10/86-एस. एस.-I]

ए. के. भट्टारार्इ, अवरोधक

स्पष्टीकरण आपन

इस मामले में छूट को भूलवली प्रभाव देना आवश्यक हो गया है, क्योंकि छूट के आवेदन-पत्र पर कार्यवाही करने में समय लगा था;

किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूलवली प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

New Delhi, the 8th October, 1986

S.O. 3634.—Whereas the Central Government is satisfied that the employees of the Field Workshop of Tuticorin Port Trust, Tuticorin are otherwise in receipt of benefits substantially similar to the benefits provided under the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 90, read with section 91A of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 915 dated 19th February, 1986, the Central Government, after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby exempts the above mentioned factory from the operation of the said Act for a period from 1st October, 1985 upto and inclusive of the 30th September, 1987.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely:—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

(2) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period: or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the said Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory;

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found in charge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document maintained in such factory establishment, office or other premises.

[File No. S-38014/10/86-SS I]

A.K. BHATTARAI, Under Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the processing of application for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 1986

आदेश

का. आ. 3634—सीमेन्ट मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन, बम्बई और इंडियन नेशनल सीमेन्ट ग्रुप एलाइड वर्क्स फैक्टरी के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और नियोजकों के उक्त एसोसिएशन तथा कर्मकारों के फैक्टरी के औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 11) की धारा 10-क

की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को माध्यस्थ के लिए निर्दिष्ट करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थ करार की एक प्रति उक्त अधिनियम की धारा 10-क की धारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार को गई है।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 10-क की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थ करार को एतद्वारा प्रकाशित करती है।

(करार)

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन पक्षकारों के नाम :

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले

1. सीमेंट मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन, एक्सप्रेस बिल्डिंग, चर्चगेट, रेलवे स्टेशन के सामने, बम्बई-400020.

कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले :

इंडियन नेशनल सीमेंट एंड एलाइड वर्कर्स फेडरेशन, मजदूर कार्यालय, कांग्रेस हाऊस, बम्बई-400004.

प्रस्तावना

इंडियन नेशनल सीमेंट एंड एलाइड वर्कर्स फेडरेशन (जिसे इसके पश्चात् आई. एम. सी. ए. डब्ल्यू. एफ. कहा गया है) ने अपने दिनांक 30 अप्रैल 1986 के पत्र संख्या एच. एफ. /7/30/4 द्वारा जो सीमेंट मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन (जिसे इसके पश्चात् सी. एम. ए. कहा गया है) को संबोधित है, दिनांक 11 जुलाई, 1983 के माध्यस्थ करार के पंचाट को समाप्त करने के अपने ह्रावे का नोटिस जारी किया। यह पंचाट भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (II) में दिनांक 20 जुलाई, 1983 की पुष्ट संख्या 1 से 82 तक प्रकाशित किया गया था।

अनुबंध "क"

और आई. एम. सी. ए. डब्ल्यू. एफ. ने अपने दिनांक 9, मई, 1986 के पत्र संख्या एच. एफ. /49/9/5 के अधीन सी. एम. ए. की दिनांक 9 मई, 1986 का मांगपत्र प्रस्तुत किया। दिनांक 9 मई, 1986 के मांग पत्र की प्रतिनिधि संलग्न है और अनुबंध "क" पर दी गई है।

अनुबंध "ख"

और सी. एम. ए. ने भी कुछ मांगें उठाई जो इसके साथ संलग्न अनुबंध "ख" में दी गई हैं।

और पक्षकारों ने इस विचार से संयुक्त विचार विमर्श किया ताकि सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुंचा जा सके ;

और सौहार्दपूर्ण समझौते के लिए बातचीत के विफल होने पर, पक्षकारों ने संबंधित विवादों को, अर्थात् आई. एम. सी. ए. डब्ल्यू. एफ. और सी. एम. ए. द्वारा उठाई गई मांगों (क्रमशः अनुबंध "क" और "ख") को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन माध्यस्थ करार को निर्दिष्ट करने का करार किया है ;

और सी. एम. ए. के अनुसार मध्यस्थों को, अन्य बातों के साथ-साथ, सीमेंट उद्योग की सामान्य आर्थिक दशा, वित्तीय स्त्रोत, अक्षा करने की क्षमता और संघटन यूनितों के उत्पादकता स्तर को ध्यान में रखना चाहिए तथा आई. एम. सी. ए. डब्ल्यू. एफ. के अनुसार, मध्यस्थों द्वारा अन्य सगत कारकों का ध्यान में रखना चाहिए ;

और पक्षकारों ने केन्द्रीय सरकार से आग्रह यह अनुरोध करने का भी करार कर लिया है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, कि आई.

एन. सी. ए. डब्ल्यू. एफ. अधिकांश कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है और सी. एम. ए. सीमेंट उद्योग में सभी नियोजकों का प्रतिनिधित्व करती है, माध्यस्थ राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए जिसमें सभी सीमेंट यूनिट हों तथा उनके सभी कर्मकार हों, और यह कि केन्द्रीय सरकार को इस प्रकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क (3-क) के अधीन अधिसूचना जारी करनी चाहिए;

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवादों को निम्न के माध्यस्थ के लिए निर्दिष्ट करने का करार किया गया है :—

1. श्री जी. रामानुजम,
2/44, रोयापेटाह हाई रोड,
मद्रास-600014
2. श्री ए. एल. कपूर,
डी एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनीज लि.,
सीमेंट हाउस,
121, महिषी कावे रोड,
बम्बई-400020

(i) निर्दिष्ट विवादग्रस्त विषय (क) क्या वे मांगें, जो दिनांक

9 मई 1986 के मांग पत्र में दी गई हैं (अनुबंध "क") न्यायोचित हैं? यदि हाँ, तो कर्मकार किम अनुलोष के हकदार हैं?"

(ख) क्या सी. एम. ए. द्वारा उठाई गई मांगें, जो इसके साथ संलग्न अनुबंध "ख" में दी गई हैं, न्यायोचित हैं? यदि हाँ, तो सीमेंट यूनितें किस अनुलोष की हकदार हैं?

(ii) विवाद के पक्षकारों का विवरण (क) सीमेंट मैनुफैक्चर्स एसो-जिममें अन्तर्बलित सिणेशन एक्सप्रेस बिल्डिंग, चर्चगेट रेलवे स्टेशन के सामने, बम्बई-400020 और पता भी सम्मिलित है:

(ख) इंडियन नेशनल सीमेंट एंड एलाइड वर्कर्स फेडरेशन, मजदूर कार्यालय, कांग्रेस हाउस, बम्बई-400040

(iii) कर्मकार का नाम, यदि वह इंडियन नेशनल सीमेंट एंड एलाइड स्वयं विवाद में अन्तर्बलित है वर्कर्स फेडरेशन

या यदि कोई संघ प्रभनगत कर्मकारों या कर्मकार का प्रतिनिधित्व करता हो, तो उनका नाम ;

(iv) उपक्रम में नियोजित प्रभा- 1,00,000 (लगभग)

वित्त कर्मकारों की कुल संख्या

(v) विवाद द्वारा प्रभावित या 1,00,000 (लगभग)

सम्भाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कल्पित संख्या ;

हम यह करार भी करते हैं कि मध्यस्थों का सर्वसम्मत विनिश्चय हम पर बाबद्धकर होगा। यदि मध्यस्थ अपने विचारों में सहमत नहीं होते हैं, तो वे ऐसे अन्य व्यक्ति को अग्रपाथ के रूप में नियुक्त करेंगे जो पारम्परिक रूप से स्वीकार्य हो तथा जिसका पंचाट पक्षकारों पर बाबद्धकर होगा।

मध्यस्थ अपना पंचाट इस करार के समुचित सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छह महीनों की अवधि या इतने और अधिक समय के भीतर वे जो पक्षकारों द्वारा पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाए।

माध्यस्थ का व्यय नियोजकों द्वारा वहन किया जाएगा। यदि व्यय के प्रश्न की स्वीकार्यता और औचित्य के बारे में कोई विवाद है, तो मध्यस्थ इस विवाद का निर्णय करेगा।

बम्बई, दिनांक 9 सितम्बर, 1986

पक्षकारों के हस्ताक्षर

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले

सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन
के लिए और उनकी ओर से

इंडियन नेशनल सीमेंट एंड एलाइड वर्कर्स फेडरेशन के लिए और उनकी ओर से

ह./-

(जे. आर. बिड़ला)

प्रेजीडेंट

साक्षी:

1. ह./-

(जी. एन. गोविल)

2. ह./-

(एस. एन. चक्रवर्ती)

ह./-

(एच. एन. त्रिवेदी)

प्रेजीडेंट

साक्षी:

ह./-

1. (सी. एल. तृधिया)

ह./-

2. (बी. एच. जोशी)

मध्यस्थों की सहमति

इंडियन नेशनल सीमेंट एंड एलाइड वर्कर्स फेडरेशन, बम्बई

प्रेजीडेंट

12-9-86

श्री एच. एन. त्रिवेदी

श्री जी. रामानुजम,

प्रेजीडेंट-इंटक,

नई दिल्ली-1

महोदय,

इंडियन नेशनल सीमेंट एंड एलाइड वर्कर्स फेडरेशन, ने भारत के सीमेंट कर्मकारों की ओर से आपके नाम का मध्यस्थ के रूप में सुझाव दिया है जैसा पहले के दो ऐच्छिक माध्यस्थों के मामले में किया था। कृपया इसकी पुष्टि करने की कृपा करें।

सादर,

आपका,

ह./-

(एच. एन. त्रिवेदी)

प्रेजीडेंट

में स्वीकार करता हूँ।

ह./-

जी. रामानुजम)

12-9-86

वी एसोसिएट्स सीमेंट कम्पनीज लि., बम्बई

ए. एन. कपूर

15 सितम्बर, 1986

निदेशक

श्री जे. आर. बिड़ला,

प्रेजीडेंट,

सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन,

एक्सप्रेस बिल्डिंग,

बम्बई-400020

महोदय,

सीमेंट उद्योग के नियोजकों और कर्मचारियों के बीच विवादप्रस्त मामलों का, जो 9 सितम्बर, 1896 को बम्बई में हस्ताक्षर किए गए माध्यस्थ करार के अंतर्गत आते हैं, समाधान करने के लिए मैं मध्यस्थ के रूप में एतद्वारा काम करने को सहमत हूँ।

भवदीय,

ह./-

(ए. एन. कपूर)

[संख्या एत-29013/5/86-डी-3 (बी)]

वी. के. शर्मा, ईस्क अधिकारी

New Delhi, the 8th October, 1986

ORDER

S.O. 3635.—Whereas an industrial dispute exists between the Cement Manufacturers' Association, Bombay and the Indian National Cement & Allied Workers' Federation, Bombay.

And whereas, the said Association of employers and Federation of workmen have by a written agreement under Sub-Section (1) of Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the said dispute to Arbitration and have forwarded to the Central Government under Sub-section (3) of Section 10A of the said Act, a copy of the said Arbitration agreement;

Now therefore, in pursuance of sub-section (3) of Section 10A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said agreement.

AGREEMENT

(Under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947)
BETWEEN

Name of the parties :

Representing Employers—Cement Manufacturers' Association, Express Building, Opp. Churchgate Railway Station, Bombay-400020.

Representing Workmen—Indian National Cement & Allied Workers' Federation, Mazdoor Karyalaya, Congress House, Bombay-400004.

PREAMBLE

Whereas the Indian National Cement & Allied Workers' Federation (hereinafter referred to as the "INCAW") by its letter No. HF/7/30/4 dated 30th April, 1986 addressed to the Cement Manufacturers' Association (hereinafter referred to as "CMA") served Notice of its intention to terminate the Award of the Boards of Arbitration dated 11th July, 1983 which Award was published in the Gazette of India Extra ordinary Part II-Section 3, Sub-section (ii) dated 20th July, 1983 from page No. 1 to 82.

And whereas the INCAWF thereafter submitted a charter of demands dated 9th May 1986 to CMA under cover of its letter No. HF 49-9-5 dated 9th May, 1986. Annexed hereto and marked as Annexure 'A' is a copy of the Chapter of Demands dated 9th May, 1986.

Annex. "A"

Annex. "B"

And whereas the CMA also raised same Demands which are contained in the Annexure "B" attached hereto.

And whereas the parties held joint negotiations with view to arrive at an amicable settlement.

And whereas on failure of the negotiation to arrive at an amicable settlement, the parties have agreed to refer the

respective dispute, viz, the demands raised by INCAWF and CMA (Annexures "A" AND "B" respectively) to the Board of Arbitration under Section 10-A of the Industrial Disputes Act, 1947.

And whereas, according to CMA the Arbitrators should take into account, amongst other matters, the general economic condition, financial resources of the Central Industrial, paying capacity and level of productivity of the constituent Units and according to the INCAWF other relevant factors have to be taken into account by the Arbitrators;

And whereas the parties have further agreed to request the Central Government that in view of the fact that the INCAWF represents a majority of workmen and the CMA represents all the employers in the Cement Industry, the arbitration should be on national level covering all the Cement Units and all their workmen and that the Central Government should therefore issue notification under Section 10A(3-A) of the Industrial Disputes Act, 1947;

It is hereby agreed between the parties to refer the following industrial dispute to the arbitration of :

- (1) Shri G. Ramanujam,
2/44, Reyapettah High Road,
Madras-600014.
 - (2) Shri A. L. Kapur,
The Associated Cement Companies Limited,
Cement House,
121, Maharshi Karve Road,
Bombay-400020.
- (i) Specific matters in dispute (a) Whether the demands as contained in the Charter of demands dated 9th May 1986 (Annexure 'A') are justified? If so, to what relief are the workmen entitled?
- (b) Whether the demands raised by CMA which are contained in Annexure 'B' attached hereto are justified? If so, to what relief are the Cement units entitled?
- (ii) Details of the parties to the disputes including the name and address of the establishment or undertaking involved.
- (a) Cement Manufacturers' Association, Express Building, Opp. Church-gate Railway Station, Bombay-400 020.
- (b) Indian National Cement & Allied Workers' Federation, Mazdoor Karyalaya, Congress House, Bombay-400004.
- (iii) Name of the workmen in case he himself is involved in the dispute or the name of the Union, if any, representing the workmen or workman in question :
- Indian National Cement & Allied Workers' Federation.
- (iv) Total number of workmen employed in the undertaking affected. 1,00,000 (Approximately)
- (v) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute. 1,00,000 (Approximately)

We further agree that the unanimous decision of the Arbitrators shall be binding on the parties. In case the Arbitrators are divided in their opinion they shall appoint another person mutually acceptable as Umpire, whose Award shall be binding on the parties.

The Arbitrators shall make their Award within a period of six months from the date of publication of this Agreement in the Official Gazette by the appropriate Government or within such further time as is extended by mutual agreement by the parties in writing.

The cost of the arbitration will be borne by the employers. If there is any dispute on admissibility and reasonableness on the question of cost, the Arbitration will decide the dispute.

Dated at Bombay, this 9th day of September, 1986.

Representing employer :	Representing of workmen
For and on behalf of the Cement Manufacturers' Association;	For and on behalf of the Indian National Cement & Allied Workers' Federation.

Sd/-	Sd/-
(J. R. BIRLA)	(H. N. TRIVEDI)
PRESIDENT	PRESENT

Witnesses :	Witnesses:
(1) Sd/- (G. L. GOVIL)	(1) Sd/- (C. L. DUDNIA)
(2) Sd/- (S. M. CHAKRAVARTHY)	(2) Sd/- (V. H. JOSHI)

**CONSENT OF ARBITRATORS
INDIAN NATIONAL CEMENT AND ALLIED WORKERS
FEDERATION, BOMBAY**

President	12-9-86.
Shri H. N. Trivedi	
Shri G. Ramanujam, President—INTUC, New Delhi.	

Respected Sir,

The Indian National Cement and Allied Workers' Federation has suggested your name as an arbitrator on behalf of the Cement Workers of India, as in the case of earlier two voluntary arbitrations. Kindly confirm here and oblige

With kind regards,

Your sincerely,

Sd/-

H. N. TRIVEDI, President

I accept

Sd/-

(G. Ramanujam)

12-9-86.

THE ASSOCIATED CEMENT COMPANIES LTD.,
BOMBAY

A. I. KAPUR
DIRECTOR

September, 15, 1986

Shri J. R. Birla,
President,
Cement Manufacturers' Association,
Express Building,
Bombay-400020.

Dear Sir,

I hereby agree to work as Arbitrator for settlement of the matters in dispute between the employers and employees in the Cement Industry covered by the arbitration agreement signed in Bombay on 9th September, 1986.

Yours faithfully,

Sd/-

(A. I. KAPUR)

[No. L-29013/5/86-DIII(B)]

V. K. SHARMA, Desk Officer.

ANNEXURE 'A'

"TRUE COPY"

INDIAN NATIONAL CEMENT AND ALLIED
WORKERS FEDERATION

PRESIDENT : H. N. TRIVEDI

Special Executive Magistrate, Ex-M.L.A.

MAZDOR KARYALAYA CONGRESS HOUSE

BOMBAY-400004

Tel. : 351809—350804

Resi. : 357658

CHARTER OF DEMANDS

DEMAND NO. 1—COVERAGE :

All the following categories of employees shall be covered under the Charter of Demands and given all benefits under the said demands from 1-7-1986 :

- A. All employees full time, part-time, seasonal permanent temporary, probationer, casual, badli, N.M. R. Trainees, apprentices, contract labour and others.
- B. All employees working in New or Old cement factories and Manufacturers, Mines, Offices, Colonies, Schools, Lifts and Recreation Clubs, etc.
- C. All employees working in Limestone, Lime-kankar, Gypsum, Laterite, Chart and Marine labour and all employees in mines, leased by the Government directly or lease obtained by the Contractors.
- D. All employees working in the limestone mines, lease obtained by the third party, where bulk quantity of the product is consumed by the Cement Company.
- E. All employees working in brick or lime Kiln operated by third party where the bulk quantity of the product is consumed by the Cement Company.
- F. All employees working on lorries, trucks, trailers etc. owned or hired by the Cement Company or by the third party but used for transport of cement limestone, bricks, lime, slag, gypsum, sea-sand fly-ash, etc.
- G. All employees working in Refractory factories manufacturing fire bricks for Kiln lining, power

house of cement factories, high alumina cement etc. where bulk of the product is consumed by cement company, including Katni Refractory Works of the A.C.C. and third party etc.

H. All employees working in Mini Cement Plants, and white cement plants and quarries connected therewith.

I. All employees working in the manufacture of building bricks used as raw material for manufacturing Pozzolona cement, which are carried on by the third party where bulk product is consumed by Cement factories.

DEMAND NO. 2—MINIMUM MONTHLY EMOLUMENTS BY WAY OF BASIC, D.A. AND H.R.A. :

Minimum total emoluments by way of Basic, D. A. and H.R.A. for an unskilled employee shall be Rs. 1817.20 per month as mentioned below with effect from 1-7-1986.

Rs. 1,060.00	Basic wage at 400 points of All India Working Class Consumers' Price Index (Base 1960=100).
Rs. 604.30	Dearness Allowance at All India Working Class Consumers' Price Index No. 628 at the rate of Rs. 2.65 per point over and above All India Working Class Consumers' Price Index of 400 (Base 1960=100).
Rs. 53.00	Additional Dearness Allowance at 5 per cent of basic wage.
Rs. 100.00	House Rent Allowance.
Rs. 1,817.20	Total per month.

DEMAND NO. 3—SCALES OF PAY :

The following scales of pay shall be introduced for all employees with effect from 1-7-1986.

E.	1,060—15—1,285 (15 years)
D.	1,100—20—1,400 (15 years)
C.	1,150—30—1,600 (15 years)
B.	1,200—45—1,875 (15 years)
A.	1,300—65—2,275 (15 years)
TC	1,100—25—1,475 (15 years)
I	1,150—35—1,675 (15 years)
II	1,200—45—1,875 (15 years)
III	1,250—55—2,075 (15 years)
IV	1,300—65—2,275 (15 years)
V	1,350—75—2,475 (15 years)
VI	1,400—85—2,675 (15 years)
VII	1,450—100—2,950 (15 years)

PIECE RATED WORKERS : The piece rates of piece rated workers shall be so fixed that they get at least 50 per cent higher emoluments than the time rated workers for same hours of work. They shall be given the minimum guaranteed total emoluments not less than the minimum total emoluments of time rated workers irrespective of their hours of work.

DEMAND NO. 4—STAGNATION AND PROMOTION INCREMENT :

All employees who reach the maximum of the grade shall be continued to be given annual increments last drawn in the grade.

DEMAND NO. 5—DEARNESS ALLOWANCE :

For the rise and fall in All India Working Class Consumers' Price Index (Base—100) beyond 400, dearness allowance shall be paid to all employees at the rate of Rs. 2.65 per point with effect from 1-7-1986.

DEMAND NO. 6—ADDITIONAL DEARNESS ALLOWANCE :

Additional Dearness Allowance shall be paid at the following rates to all employees with effect from 1-7-1986.

- 5 per cent of Basic wages to employees in Grade E.
- 10 per cent of Basic wages to employees in Grade D&C.
- 15 per cent of Basic wages to employees in Grades B&A and all T.C. Clerical Lower Technical and Supervisory Staff.

The existing Special D.A. of Rs. 8.50 per month paid to T.C., Clerical and other staff shall be increased to Rs. 50/- per month with effect from 1-7-1986.

DEMAND NO. 7—HOUSE RENT ALLOWANCE :

All employees shall be paid monthly House Rent Allowance as under with effect from 1-7-1986 :

- Rs. 100.00 to employees in E&D Grades
- Rs. 125.00 to employees in C&TC Grades
- Rs. 150.00 to employees in B, I and II Grades
- Rs. 175.00 to employees in A, III & IV Grades
- Rs. 200.00 to employees in V, VI, VII Grades

DEMAND NO. 8—HOUSE RENT ALLOWANCE :

House rent recovery for the quarters provided by the Company shall not be increased beyond the present quantum.

DEMAND NO. 9—GUARANTEED INCREASE, ADJUSTMENT & SERVICE-WEIGHTAGE :

All employees shall be given a salary increase of not less than Rs. 725/- per month as Guaranteed increase. The Guaranteed increase shall be added to the existing total emoluments of the employees as on 30-6-1986 consisting of Basic Wage, Dearness Allowance, Additional Dearness Allowance, House Rent Allowance. The new total emoluments shall be reworked into the new basic wages/salary, dearness allowance, additional dearness allowance and house rent allowance. This may be done by first deducting the minimum house rent allowance payable to the unskilled workers, then deducting D.A. & Addl. D.A. Payable to the unskilled workers at All India Working Class Consumers' Price Index 628 and the balance will be treated as the basic wage of an employee. Thereafter if the basic wage of an employee falls below the minimum of the new grade as a result of such reworking, his basic wage shall be brought up to the minimum of the grade applicable. If the basic wage falls between the two steps in the revised demanded grade applicable, it shall be brought up to the next higher step in the new grade. After arriving at the new basic wages as mentioned above, one increment in the new scales for every two years of service shall be added to the basic wages as service weightage. The adjusted basic wage, D.A., and Addl. D.A., and H.R.A., shall be paid to all the employees as demanded with effect from 1-7-1986.

DEMAND NO. 10—CITY ALLOWANCE :

All employees working in those factories, quarries and offices which are situated near Cities, Towns and Holy places or hill stations shall be paid City Allowance at the rate of 10 per cent of total salary with allowances per month with effect from 1-7-1986.

DEMAND NO. 11—HEAT ALLOWANCE :

All employees shall be paid Heat Allowance at the rate of 10 per cent of their basic wage per month with effect from 1-7-1986.

DEMAND NO. 12—DUST ALLOWANCE :

All employees shall be paid dust allowance at the rate of 10 per cent of total salary with allowances per month with effect from 1-7-1986.

DEMAND NO. 13—HEAVY DUTY ALLOWANCE :

All drivers, operators of Dozer, Truck, Lorry, Bus, Dumper, Fork-lift truck, Shovel, Halco Drill, Loco, all

types of Cranes irrespective of capacity, Scraper or Crusher, or any other Heavy Earth Moving machinery shall be paid Heavy Duty Allowance at the rate of 10 per cent of total salary with allowances per month with effect from 1-7-1986.

DEMAND NO. 14—NIGHT SHIFT ALLOWANCE :

Employees working in Shifts at any time between 6. p.m. and 7 a.m. shall be given Night Shift Allowance at the rate of Rs. 5/- per shift with effect from 1-7-1986.

DEMAND NO. 15—CONVEYANCE ALLOWANCE :

Conveyance allowance shall be paid as under to all employees with effect from 1-7-1986.

Rs. 250/- per month to employees who have Scooter or Moped.

Rs. 100/- per month to all other employees.

DEMAND NO. 16—LONG DISTANCE ALLOWANCE :

Employees who are coming to duty from a distance of 5 kms. or more, shall be given long distance allowance of Rs. 10/- per day with effect from 1-7-1986.

DEMAND NO. 17—CASH HANDLING ALLOWANCE :

Employees who are handling cash for disbursement of salaries on pay day shall be given an allowance @ Rs. 50/- per day on pay day with effect from 1-7-1986.

DEMAND NO. 18—ACTING ALLOWANCE :

If an employee works or officiates in place of another employee in a higher grade or post, he shall be paid acting allowance equal to the difference between the total emoluments of the employee in whose place he works or officiates and his own total emoluments or 15 per cent of his total emolument whichever is higher. The Acting Allowance shall be paid to an employee even if he works or officiates for a day or more in a higher post or grade with effect from 1-7-1986.

DEMAND NO. 19—EDUCATION ALLOWANCE :

Education Allowance shall be paid to all employees for education for self, children, spouse of the employee at the rate of Rs. 200/- per month per head with effect from 1-7-1986.

Demand No. 20—Leave Travel Allowance :

One month's total emoluments shall be paid to all employees once a year as leave travel allowance, unconditionally with effect from 1-7-1986. This shall be allowed to be accumulated for three years.

Demand No. 21—Incentive Scheme :

Incentive scheme shall be introduced in all the factories, quarries, offices, etc. as under with effect from 1-7-1986.

- A. Where capacity utilisation is above 75 per cent and below 85 per cent of installed capacity, 10 per cent of total emoluments.
- B. Where capacity utilisation is above 85 per cent and below 95 per cent of installed capacity, 15 per cent of total emoluments.
- C. Where capacity utilisation is above 95 per cent and below 100 per cent of installed capacity, 20 per cent of total emoluments.
- D. Where capacity utilisation is 100 per cent and above, of installed capacity, 25 per cent of total emoluments.

Demand No. 22—Leave facilities :

15 days privilege leave, 10 days sick leave and 5 days casual leave with full pay and allowances shall be added to

the existing quantum of leave facilities for all employees. Privilege, Casual and Sick leave shall be allowed to be accumulated or encashed at the option of the employee at any time. Casual, Temporary, badli workers etc. who have worked for less than 240 days in any year shall be allowed leave facilities pro-rata.

All workers under Contractors if any etc. shall be given privilege, casual and sick leave as given to other departmental employees of the Company the leave facilities shall be with effect from 1-7-1986.

Demand No. 23—Bank and Festival Holidays :

All employees shall be given all Bank and Festival Holidays with full pay and allowances with effect from 1-7-1986.

All employees shall be given one day's total salary and all allowances or given one day's extra paid leave when a Bank or a Festival holiday falls on their weekly offs.

Demand No. 24—Special Leave for Office Bearers:

Office bearers of the recognised Unions and the Federation shall be given special leave of 10 days with full pay and allowances in a month to attend Union or Federation meetings at a Regional or all India levels or for Union or Federation work and to attend conciliation etc.

Demand No. 25—Uniforms, Shoes & Socks :

All employees shall be supplied with four pants and four shirts of terry cotton and for female employees four saris, blouses and petty cots every year, with effect from 1-7-1986.

All employees shall be supplied with two pairs of shoes and four pairs of socks every year and female employees shall be supplied with two pairs of chappals every year with effect from 1-7-1986.

Demand No. 26—Washing Allowance :

All employees shall be paid Rs. 30 per month as washing allowance with effect from 1-7-1986.

Demand No. 27—Five Day Week :

Five day week shall be introduced in all the cement plants and quarries including Offices for all employees without any reduction in their monthly regular emoluments.

Demand No. 28—Over Time :

If an employee is asked to work more than 8 hours a day, he shall be paid overtime at twice the normal rate of pay, including all allowances. If an employee is asked to work on a weekly off or on a Festival or Bank Holiday, he shall be paid overtime at twice the normal rate of pay including all allowances in addition to extra one day's full pay and allowance. This will be in addition to any other allowances paid to him. This shall be with effect from 1-7-1986.

Demand No. 29—Loan for Vehicles :

Interest free loans for purchasing vehicles shall be given to all employees as under :

Rs. 10,000/- for Scooter

Rs. 5,000/- for Moped

Rs. 1,000/- for Bicycle

Demand No. 30—Housing Loan :

All employees shall be given housing loan equivalent to his 40 months' total emoluments free of interest for construction or repair of his house, etc. The recovery of the amount may be made in 180 equal monthly instalments.

Demand No. 31—Food Grain Advance :

All employees shall be given an advance of two month's total salary including all allowance, free of interest per year

to purchase seasonal grains such as wheat, rice, groundnut oil, etc. and it may be recovered in twelve equal monthly instalments.

Demand No. 32—Provident Fund :

Provident Fund contributions both from the employers and the employees shall be 10 per cent each of the total salary with all allowances with effect from 1-7-1986.

Demand No. 33—Gratuity :

With effect from 1-7-1986, gratuity at the rate of one month's salary including all allowances, shall be paid (last drawn) to all employees for every year of service in case of death, retirement, resignation, disability to continue further in service, termination of service for any reason whatsoever.

Demand No. 34—Retirement age :

No employee shall be retired before he reaches the age of 65 years.

Demand No. 35—Pension :

Pension Scheme shall be introduced for all employees as under :

- (a) If an employee retires after superannuation, he shall be paid pension equivalent to 50 per cent of his monthly salary including all allowances shall be paid as pension till his death.
- (b) If an employee retires after 30 years of service, he shall be paid pension equivalent to 75 per cent of his monthly salary including all allowances till his death.
- (c) If an employee dies while in service, an equivalent to 75 per cent of his monthly salary including all allowances shall be paid to his widow till her death and to his children till they attain the age of 21 years.
- (d) If an employee retires prematurely on Medical grounds, he shall be paid Pension equivalent to 75 per cent of his monthly salary, including all allowances till his death.

Demand No. 36—Medical Benefit :

Full reimbursement of the medical bills of employees and their family members shall be made within one week from submission of the bills. This shall be with effect from 1-7-1986.

Demand No. 37—Departmental Labour :

All work connected with manufacturing process, repairs of machinery, roads for loading and unloading of coal, cement, all types of raw materials, gunny bags, cleaning, etc. shall be carried out by the departmental labour only.

All employees at present working under the contractors shall be absorbed as permanent employees with continuity of service in the Company.

Demand No. 38—Casual, Badli, Temporary Labour :

All casual, badli, temporary employees working on process jobs shall be made permanent.

Demand No. 39.—Contract Labour:

No contract labour shall be allowed to work inside of outside the factory or mine or quarry or on the repair job of roads, connecting roads where Company's dumpers or trucks ply to feed limestone to crushing plant, gunny bags, cleanings, etc. No contract labour shall be allowed for minor and major repairs of machinery including ropeway or in manufacturing process.

Demand No. 40.—Promotion:

All employees shall be promoted to a higher grade atleast after every 10 years of service.

Demand No. 41.—Recruitment :

Atleast one son or daughter or dependent of every employee shall be given employment in the Company within one month after the retirement of the employee or after the death of the employee while in service, or fatal accident or resignation of an employee after 10 years of service.

Demand No. 42.—Cement at Concession:

For building or repairing the house of the employees, they shall be given upto 300 bags of cement at a discount of 25 per cent of ex-factory levy price.

Demand No. 43.—Long Service Award:

All employees who put in long service in the Company shall be given long service awards as under:

- A. Those who put in 15 years' service, one month's total salary with all allowances.
- B. Those who put in 25 years' service 1-1/2 month's total salary with all allowances.
- C. Those who put in 30 years' or more service, two month's total salary with all allowances.

Demand No. 44.—Nomenclature:

Nomenclatures and fitments and grades shall be revised as per the ANNEXURE.

Demand No. 45.—Participation of Labour in Management:

A Scheme for effective participation of labour in management shall be introduced in all cement factories and quarries at all levels including the Board of Directors.

Demand No. 46.—Effect:

All demands shall be given with effect from 1-7-1986.

Demand No. 47.—Interim Relief:

All employees shall be given interim relief of Rs. 800/- per month with effect from 1-7-1986.

Demand No. 48.—Monthly Paid System:

All employees shall be brought under monthly paid system with all consequential benefits.

**Demand No. 49.—Machinery To Resolve
DISPUTES :**

A. For clarification, interpretation or removal of any doubts or ambiguity in any of the terms of award or settlement, the same shall be referred to voluntary Arbitration.

B. With a view of avoid confrontation and disputes in connection with proper, effective and speedy implementation of any of the terms of settlement or award, there shall be an appropriate bipartite machinery with equal representatives of workers and management.

Demand No. 50.—Existing Rights And Benefits:

All existing reights, benefits and privileges etc. which are more favourable shall not be adversely affected.

Sd/-

(H.N. TRIVEDI), President
Indian National Cement & Allied
Workers' Federation.

9-5-86

Indian National Cement & Allied Workers' Federation
ANNEXURE

Sl. No.	Occupational Nomenclature	Demanded Grade
1	2	3
1.	Armature Winder	V & VI
2.	Ayah	I & II
3.	Auxiliary Nurse	III
4.	Bags Brander	C
5.	Bearer	B
6.	Boiler Attendent	V, VI, VII
7.	Cable Joiner	(a) V & VI

1	2	3
8.	Canteen Vendor	D & C
9.	Carpenter	(b) A & V
10.	Cook	B & A
11.	Crane Driver	A & V
12.	Crusher Operator	A & V
13.	Diesel Mechanic	A & V & VI
14.	Dryer Operator	A & V
15.	Electrician-cum-Wireman	V & VI
16.	Electrician	VI & VII
17.	Gangman	B & C
18.	Hammerman	C
19.	Havildar/Jamader	A & V
20.	Security Supervisor	VI & VII
21.	Instrument Mechanic	V & VI
22.	Khalasi	B & A & V
23.	Lab Boy	C & B
24.	Loco Driver	A & V
25.	Loco Fireman	B
26.	Operator	B & A
27.	Plant Operator	B & A
28.	Mali	B
29.	Mason	B & A & V
30.	Mazdoor/Helper	E & D
31.	Packing Loader	D & C
32.	Bucket Loader	B & A
33.	Pay Loader	D & A
34.	Shift Incharge Cement Mill Raw Mill Coal Mill	VI & VII
35.	Motor Vehical Driver	A & V
36.	Packer Man	B, A & V
37.	Nodulizer Operator	B & A
38.	Painter	B & A
39.	Peon	C & B
40.	Points Man	B & A
41.	Heavy Equipment Operator	A & V
42.	Blaster	B & A
43.	Sticher	B & A
44.	Sweeper	E & D
45.	Switch Board-Turbine Attendent	A & V
46.	Testing Boy	B & A
47.	Ward Boy	E & D
48.	Washer Man	C & B
49.	Black Smith	B, A & V
50.	Fitter	B, A & V
51.	Machine Tool Operator Turnor Machnist Driller/Plaining Shaping/Milling Sawing Man	B, A & V
52.	Machinery Attendent	C & B
53.	Miller	A & V
54.	Moulder	B & A & V
55.	Quarry Driller	B, A & V
56.	Welder	B & A & V
57.	Stores Issuer	Tc & J
58.	Dresser	II & III
59.	Midwife	III & IV
60.	Clerk General	III & IV
61.	Sr. Clerk/St. Assistant	VI & VII
62.	Tester-cum-Gauger Quality & Process Controller	V & VI
63.	Typist/T.P. Operator/Telex	IV & V
64.	Steno Typist/Stenographer	V & VI
65.	Telephone Operator	IV & V
66.	Time Keeper	IV & V

1	2	3
67. Sr. Time Keeper		VI & VII
68. Pr. Trained Teacher		III & IV
69. Tracer		II & III
70. Loading Supervisor		II & III
71. Pharmacist		V & VI
72. Secondary Trained Teacher		VI & VII
73. Mining Mate		XII & VII
74. Sanitary Inspector		V & VI
75. Trained Teacher		VI & VII
76. Shift Incharge/Packing House		VI & VII
77. Charge Hand		VI
78. Yard Supervisor		VI & V
79. Blasting Supervisor		VI & VII
80. Lab Asstt.		VII
81. Lab Technician		VI & VII
82. Nurse Male-Female		V & VI
83. Tariff In charge		VI & VII
84. Canteen Supervisor		V & VI
85. Statistician		VII
86. Burner		VI
87. Shift Incharge Burner		VII
88. Asstt. Foreman		VII
89. Overseer		VII
90. Chief Time Keeper		VII
91. Asstt. Accountant		VII
92. Asstt. Store-Keeper		VII
93. Cashier		VII
94. Draftsman		VII
95. Auto Electrician		A & V
96. Seal Man		C
97. Librarian		VI & VII
98. Project Operator		V
99. Rope Operator		B & V
		Sd/-

H.N. TRIVEDI President,
Indian National Cement & Allied
Workers Federation
9-5-86

ANNEXURE "B".

DEMANDS CHARTER OF CEMENT MANUFACTURERS' ASSOCIATION

Demand No. 1.—Productivity Studies.

Any increase in wages shall be related to increase in productivity at each unit and to achieve this, joint productivity studies under the guidance of National Productivity Council or any other similar body be undertaken by a joint team comprising the representatives of the employer and workmen at local level and the recommendations of the study team shall be implemented in consultation with the recognised Union.

Demand No. 2.—Rational Job Combination.

For optimum utilisation of manpower and improving productivity, rational job combination shall be introduced.

Demand No. 3.—Multi-craft Job Orientation.

Multi-craft Job Orientation programme shall be introduced to enable workmen to acquire skills in more than one trade for optimum utilisation of existing manpower.

Demand No. 4.—Modernisation/Mechanisation, etc.—Surplus Labour.

As a result of modernisation/mechanisation/introduction of improved technology, any surplus labour force resulting there-

from shall be deployed on available jobs in the same Unit or in any other Unit belonging to the Company without detriment to their emoluments.

Demand No. 5.—Medical Care/Specialist/Medical Treatment.

(a) Employers shall have no obligation whatsoever to provide any medical care/specialist medical treatment to the employees and their dependants covered by the ESI.

(b) In case of employees not covered by ESI, for providing specialised in-patient treatment to him or to his dependants a reasonable amount of reimbursement not exceeding Rs. 2,500/- in a block period of three years be provided.

Demand No. 6.—Canteen.

Canteen shall be run on "no profit-no loss" basis and accordingly prices of items served in the Canteen shall be revised periodically.

Demand No. 7.—Use of electricity for domestic purposes.

To avoid indiscriminate use of electricity, reasonable limit on consumption of electricity be fixed and electricity consumption beyond the said reasonable limit be charged at actual cost to the employee.

Demand No. 8.—Wilful and deliberate 'Go-Slow' tactics

Without prejudice to the employer's right to take suitable disciplinary action, workmen who resort to wilful and deliberate 'go-slow' tactics shall be paid only pro-rata wages based on actual output.

Demand No. 9.—Accident leave.

(a) There should be a waiting period as provided under the ESI Act/Workmen's Compensation Act for treating the period of absence from duty as accident leave with pay.

(b) The amount of compensation payable for total/partial permanent disablement shall be paid after setting off the amount of fortnightly compensation payable under the Workmen's Compensation Act as provided under the said Act.

Demand No. 10.—Sick units.

What relief should be given to sick units.

Demand No. 11.—Dust Allowance.

In such of the cement plants where Pollution Control Equipments have been installed and are in operations, there is no justification for continuing to pay Dust Allowance, except in packing house, and the same should be discontinued

Demand No. 12.—Heat Allowance.

In such of the cement plants where Centralised Instrumentation Control System has been installed, there is no justification for payment of Heat Allowance and the same be discontinued.

Demand No. 13.—New Units.

In case of New Units 75 per cent of award rates of wages be paid for a period of 24 months from the date of commencement of commercial production, or till such time they attain 85 per cent capacity utilisation, whichever is earlier.

Demand No. 14.—Classification of Cement Units

Classification of Cement Units be made on various considerations and merits including manhours per tonne of cement.

For Cement Manufacturers' Association

Sd/-

J.R. BIRI A. President